RNI NO. RAJHIN/2013/57419

जयपुर
शनिवार
03 अगस्त, 2024

वर्ष: 10 : अंक: 108

राजस्थान का सर्वाधिक ई-पेपर दैनिक

द पुलिस पोस्ट

अंदोलन नहीं अखबार

जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा से प्रसारित

दूरभाष: 01482 : 453184 : पृष्ठ: 08 : मूल्य: 1.50 रुपए

सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा

आमजन से सरोकार रखने वाले विभागों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : भजनलाल शर्मा

जलदाय विभाग के सांगानेर एईएन और जेईएन को हटाया

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रशासन आमजन की हर समस्या के समाधान का अंतिम पड़ाव है। ऐसे में वे राज्य सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन से सरोकार रखने वाले विभागों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे न केवल नियमित रूप से जनसुनवाई करें बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कर उन्हें सूचित भी करें। भजनलाल शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में गति लाने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य के विकास और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सांगानेर-प्रताप नगर में 132 केवी जीएसएस का निर्माण, विद्युत लाइनों को भूमिगत करना तथा कृष्णा सिटी, बालाजी विहार, नीमडी वाले बालाजी पत्रकार कॉलोनी रोड व चकरोल रामनगरिया विस्तार में 33 केवी सब स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही को समयबद्ध पूरा करें। मुख्यमंत्री ने भांकरोटा फ्लाई ओवर व कमला नेहरू फ्लाई ओवर का शेष कार्य शीघ्रता से पूरा करवाने के लिए इसकी नियमित मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा व स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन व नगरीय विकास विभाग से संबंधित 1913 करोड़ रुपए से अधिक के 65 कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेडीए और नगर निगम समन्वय बना कर साफ-सफाई, सीवरेज, सड़क सहित विभिन्न कार्यों को पूरा करें ताकि आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सांगानेर स्टेडियम के समुचित विकास और क्षेत्र के पार्कों का उचित रख-रखाव किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 'विरासत भी, विकास भी' के विजन को ध्यान में रखते हुए सांगानेर क्षेत्र के पुरातात्विक महत्व के गेटों की मरम्मत कर इनका सौंदर्य कार्य करवाया जाए।

द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यीकरण में लाएं गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि द्रव्यवती नदी जयपुर के एक बड़े हिस्से से होकर गुजरती है। बजट में द्रव्यवती नदी का विकास करने के लिए नवीन योजना बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित कर समय पर इसका सौन्दर्यकरण तथा मरम्मत सुनिश्चित करें। शर्मा ने राजस्व, स्वायत्त शासन, जल संसाधन तथा नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों को भी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने भी बैठक में शामिल होकर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अपना फीडबैक दिया। बैठक में कमला नेहरू नगर स्थित नाले पर आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिया निर्माण, डिग्गी रोड तक 2 किमी लिंक रोड को 200 फीट चौड़ा करने, पृथ्वीराज नगर (उत्तर) में ड्रेनेज एवं सीवरेज की समुचित व्यवस्था, सांगानेर में मिनी सचिवालय बनाए जाने, महारानी फार्म-अग्रवाल फार्म की पुलिया की ऊंचाई बढ़ाने, सांगानेर में जैन अतिशय क्षेत्र के रास्ते में से मीट की दुकानों को दूर हटवाने के सुझाव भी प्राप्त हुए। इस अवसर पर मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रवीण गुप्ता, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण न हो अनावश्यक देरी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रोजेक्ट्स में अनावश्यक देरी को कम करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाए। साथ ही, नियमित अंतराल में प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए हर 15 दिन में संबंधित एजी-एएजी के साथ बैठक कर ऐसे प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की जाए। भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नल कनेक्शन के आवेदन लम्बित होने पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्र के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता को काम में लापरवाही के चलते हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को शिविर लगाकर लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने नल कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए।

राज्य सरकार की राशन डीलरों से वार्ता जारी

प्रदेश में राशन वितरण की व्यवस्था शीघ्र होगी सुचारू: गोदारा

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था सुचारू करने के लिए राज्य सरकार की ओर से राशन डीलर्स से उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का समाधान कर नियमित राशन वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा व उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए राज्यस्तरीय फेसिलिटेशन एण्ड मीडिएशन सेंटर के भवन निर्माण के लिए 19 अक्टूबर, 2015 को जयपुर में भूमि आवंटित की गई। वर्ष 2023-24 के बजट में इस भूमि पर भवन की घोषणा की गई, लेकिन बजट के अभाव में इसका कार्य नहीं हो पाया। इससे पहले विधायक गोपाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की 25 हजार 500 सक्रिय राशन की दुकानों पर उपलब्ध करवाकर नवीन 4जी पॉईंट ऑफ सेल से जोड़ा जा चुका हैं। इन शेष दुकानों के सक्रिय होने पर आवश्यकतानुसार नवीन 4जी पॉईंट ऑफ सेल से जोडे जाने के लिए समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यह सेन्टर हसनपुरा जयपुर में आवंटित भूमि पर निर्मित किया जाना है, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में इस पर कोई राशि व्यय नहीं की गई।

इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए कैप्टन शुभांशु शुक्ला होंगे भारतीय यात्री

द पुलिस पोस्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुन लिया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से इस मिशन के मुख्य अंतरिक्ष यात्री होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत-अमेरिका मिशन पर उड़ान भरने के लिए अपने अंतरिक्ष यात्री-नियुक्तों में सबसे कम उम्र के व्यक्ति को मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। भारतीय वायुसेना में शुक्ला को हाल ही में प्रोमेशन मिला था। इसरो ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) भेजेगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (एचएसएफसी) ने आईएसएस के लिए अपने आगामी एक्सिओम-4 मिशन के लिए अमेरिका स्थित एक्सिओम स्पेस के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता (एसएफए) किया है। इसमें दो भारतीय मुख्य और बैकअप मिशन पायलट होंगे। बयान के अनुसार, ग्रुप कैप्टन शुक्ला प्राइमरी मिशन पायलट होंगे, जबकि भारतीय वायु सेना के एक अन्य अधिकारी, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, बैकअप मिशन पायलट होंगे। इन्हें गगनयात्री के नाम से जाना जाएगा। इन अधिकारियों की ट्रेनिंग अगस्त महीने के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। मिशन के दौरान, अधिकारी आईएसएस के लिए चुने गए साइंटिस्टों के साथ रिसर्च और टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रयोग करेंगे। साथ ही स्पेस आउटरीच एक्टिविटीज में भी शामिल होंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में जन्मे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायु सेना में अपना सफर लगभग 18 साल पहले शुरू किया था। उन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में ट्रेनिंग ली है। ग्रुप कैप्टन शुक्ला के परिवार के अनुसार कारगिल के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी

कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को केबिनेट और मंत्री परिषद् की बैठक बुलाई है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट बीते दिनों पेश किया है। अब इस बजट के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री इस बैठक में मंत्रियों से चर्चा करेंगे। इसके लिए दिसंबर में होने वाले इनवेस्मेंट समिट की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी।

बैठक में इन विषयों पर हो सकती है चर्चा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शाम 5 बजे कैबिनेट की और 5:30 बजे मंत्री परिषद् की बैठक होगी। इस बैठक को लेकर कोई निश्चित एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बजट में हुई घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर इन बैठकों में चर्चा होगी। इस दौरान 9 से 11 दिसंबर को 'राजस्थान राइजनिंग इन्वेस्टमेंट समिट' को लेकर भी चर्चा होगी। यह समिट राजस्थान की अर्थव्यवस्था और उद्योगों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण आमजन को काफी नुकसान पहुंच रहा है, ऐसे में आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए भी चर्चा होगी।

सरकार का उद्देश्य बजट की योजना का लाभ हर आमजन को मिले

राजस्थान में भजन लाल सरकार ने बीते दिनों अपना बजट पेश किया। बजट में कई नई योजनाओं को लेकर घोषणाएं की गई। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल चाहते हैं कि बजट की सभी योजनाओं का लाभ हर आम जनता तक पहुंचे। इसको लेकर कल होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर कोर्ट ने उठाए सवाल

द पुलिस पोस्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का आदेश देने से इन्कार कर दिया हो लेकिन इस वर्ष परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को कठघरे में खड़ा किया है। कोर्ट ने एनटीए के आचरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक हुई चर्चा से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि नीट की शुचिता प्रणालीगत स्तर पर दूषित हुई, लेकिन एनटीए ने इस वर्ष जिस तरह परीक्षा कराई है, वह गंभीर चिंताओं को जन्म देता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह बहाना नहीं हो सकता कि परीक्षा हजारों सेंटर पर हुई थी या परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। नीट जैसी परीक्षा आयोजित करने के लिए एनटीए के पास पर्याप्त फंडिंग, समय और मौका था। सर्वोच्च अदालत ने भविष्य में परीक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की नसीहत देते हुए कहा कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों का भरोसा जगे।

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया कमेटी का दायरा

एनटीए में सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कमेटी का दायरा बढ़ाते हुए कमेटी से परीक्षा को फूलग्रुफ बनाने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर विचार कर रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने यह भी बताया है कि किन किन पहलुओं पर कमेटी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का समय बढ़ाते हुए उसे 30 सितंबर तक शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा मंत्रालय एक महीने में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर निर्णय लेगा। सिफारिशों पर अमल के बारे में निर्णय लेने के दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगा। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने नीट में गड़बड़ियों और पेपर लीक मामले में दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि कई चीजें ऐसी हैं जिसके कारण नीट पर सवाल खड़ा होता है। प्रश्नपत्र पटना और हजारीबाग में लीक हुआ। एक केंद्र में स्ट्रांग रूम का पीछे का दरवाजा खुला था और अनधिकृत व्यक्ति को प्रश्नपत्र मिला। इससे संकेत मिलता है कि सुरक्षा में गंभीर खामी थी। एनटीए को प्रभावी और कड़े सुरक्षा मानकों को लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि ये भी पता चला कि प्रश्नपत्र ई-रिक्शा से भेजे गए और प्राइवेट कोरियर कंपनियों की सेवाएं ली गईं। याचिकाकर्ता ने सही मुद्दा उठाया है कि एनटीए ने परीक्षा के बाद ओएमआर शीट सील करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया था। निश्चित टाइम तय न होने से बेइमान लोग छात्रों की ओर से ओएमआर शीट जमा करने के बाद उसमें हेरफेर कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि दूसरा चिंता का विषय यह है कि एनटीए ने उस लोगों पर भरोसा किया जिन पर वह सीधी नजर नहीं रख सकता था। कोर्ट ने कहा कि कई तरीके अपनाए जा सकते थे जिससे परीक्षकों पर नजर रखना सुनिश्चित होता और अनियमित तरीकों की गुंजाइश कम होती। इतना ही नहीं कोर्ट ने गलत प्रश्नपत्र बांटे जाने और ग्रेसमार्क का मुद्दा भी उठाया है। कोर्ट ने एनटीए से विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार करके एक प्रोटोकाल तैयार करने को कहा है। कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि फैसले में उठाए गए सभी पहलुओं पर वह ध्यान दे। साथ ही केंद्र की ओर से गठित कमेटी से भी सिफारिश करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखने को कहा है।

पीएचडी मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार

जलदाय विभाग में हैल्पर, जेईएन सहित 25 हजार पदों पर भर्ती शीघ्र: कन्हैयालाल

भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को चेतावनी: कार्रवाई के लिए रहे तैयार

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। प्रदेश के युवाओं के लिए खुश खबर है। जलदाय विभाग में हैल्पर, जेईएन, एईएन सहित 25 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसका संकेत पानी पर बहस का जवाब देते हुए मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने दिए। उन्होंने कहा कि मैं 40 लापरवाह अफसरों को सस्पेंड कर चुका। अगर मैं अंदर तक गया तो मेरे विभाग में एक भी नहीं बचेगा। इस लेवल का भ्रष्टाचार है। ज्यादा मैं कह नहीं सकता। मेरे पास विभाग है, मुझे विभाग को भी चलाना है। इसके साथ ही पानी पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन पानी पैदा नहीं कर सकते। पानी खत्म हो जाएगा तो बालाजी महाराज ही वापस ला सकते हैं। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस राज में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ। पानी योजना बना दी गई, पता ही नहीं उनमें पानी कहां से आएगा? केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन में जो फंड दिया, उसका 20 फीसदी ही खर्च कर सके थे। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पोंग बांध (हिमाचल प्रदेश) और दूसरे बांधों में पानी कम हो रहा है। पोंग बांध में कम पानी चिंताजनक है। मैं तो कहूंगा कि बालाजी महाराज जल्दी इनको भर दें, नहीं तो आने वाले समय में यह समस्या बहुत विकराल होने वाली है। आने वाले समय में हम इस पर कदम उठाएंगे। पानी खत्म हो जाएगा तो बालाजी महाराज ही ला सकते हैं। जलदाय मंत्री ने कहा कि हम बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन पानी पैदा नहीं कर सकते। पानी खत्म हो जाएगा तो बालाजी महाराज ही वापस ला सकते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कमेंट कर रहे थे, बार-बार बालाजी महाराज को टारगेट कर रहे थे। सिर्फ एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इन्होंने बालाजी पर ही विश्वास करना छोड़ दिया। जलदाय मंत्री ने विभाग में खाली पड़े पदों पर जल्द भर्ती करने का दावा किया। मंत्री ने कहा कि विभाग में हैंडपंप और ट्यूबवेल की मरम्मत के लिए तकनीकी हैल्पर, जेईएन और एईएन के पदों पर भर्ती की जाएगी। करीब 25 हजार पदों पर भर्ती होगी।

केंद्र और राज्य सरकार के बीच बने प्रभावशाली माध्यम बने राज्यपाल: मोदी

द पुलिस पोस्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। राज्यपाल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यपालों के आग्रह किया कि वे सभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक असरदार पुल की भूमिका निभाएं। पीएम ने राज्यपालों से कहा कि लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ इस तरह से बातचीत करने का आग्रह किया, जिससे वंचित लोगों को शामिल किया जा सके। बता दें कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वहीं इस सम्मेलन को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, शनिवार को खत्म होने वाले इस सम्मेलन में ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो न केवल केंद्र-राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सत्र के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कई केंद्रीय एजेंसियां सभी राज्यों में बेहतर समन्वय के साथ काम करें। उन्होंने राज्यपालों को सलाह दी कि वे इस बारे में सोचें कि वे अपने-अपने राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में इस समन्वय को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस सम्मेलन के एजेंडे में सावधानीपूर्वक चुने गए मुद्दे शामिल हैं, जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी राज्यपाल लोगों की सेवा और कल्याण में योगदान देना जारी रखेंगे, उन्होंने जो शपथ ली है, उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और राज्यपाल 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को बड़े पैमाने पर जन आंदोलन बनाकर इसमें योगदान दे सकते हैं।

उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री ने भी सत्र को किया संबोधित

वहीं अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपालों की शपथ का जिक्र किया और उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं और पिछले दशक के दौरान हुए अविश्वसनीय विकास के बारे में लोगों को जागरूक करने की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने का आग्रह किया। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं की रूपरेखा बताई और राज्यपालों से लोगों में विश्वास पैदा करने और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 'जीवंत गांवों' और 'आकांक्षी जिलों' का दौरा करने का आग्रह किया।

सम्मेलन में अलग-अलग सत्र किए जाएंगे आयोजित

राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सम्मेलन में अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राज्यपालों के उप-समूह प्रत्येक एजेंडा आइटम पर विचार-विमर्श करेंगे। राज्यपालों के अलावा, ऐसे सत्रों में केंद्रीय मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल होंगे। शनिवार को समापन सत्र के दौरान उप-समूहों की टिप्पणियों और सुझावों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ-साथ अन्य प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने दिया ज्ञापन

द पुलिस पोस्ट

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टोंक नगर इकाई ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक के प्राचार्य को ज्ञापन दिया तथा बताया कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक जिले का सबसे बड़ा तथा सबसे पुराना महाविद्यालय है और इसका भवन भी अत्यधिक पुराना होने के कारण जर्जर अवस्था में है अतः महाविद्यालय की निम्न समस्याओ से प्राचार्य को अवगत कराया।

1. महाविद्यालय में आगे का ऊपरी भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है जिससे विद्यार्थियों की जान का खतरा हमेशा बना रहता है।2. महाविद्यालय में भवन अपर्याप्त है अतः प्रशासनिक भवन की आवश्यकता है

3. महाविद्यालय में कुछ व्यवस्था कोर्स जैसे BBA, MBA, BCA, BA.Bed , Bsc.Bed चार्ज वार्षिक कोर्स संचालित करवाने की आवश्यकता है विदेशी भाषा कोर्स ।

4. महाविद्यालय खेल मैदान की चार दिवारी की अत्यधिक आवश्यकता है

5. पुस्तकालय कर्मचारी एवं पीटीआई शारीरिक शिक्षक के पद खाली होने के कारण महाविद्यालय की अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित नहीं है

अतः महाविद्यालय की उक्त समस्याओं का समाधान होना अति आवश्यक है क्योंकि महाविद्यालय जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है महाविद्यालय से दूर - दरार गांव के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं । अतः शीघ्र उक्त समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश देवन्दा एबीवीपी जिला संयोजक अजय डोई, अमन सैनी, आर्यन लखेरा, हेमंत ग्वाला, विशाल मेहरा, किरन शर्मा, दीपांशु , दीपक, पंकज गुर्जर, अंजलि, दीपशिखा, खुशी, फरहीन, मीना, भूमिका, दिलखुश, संजय, दिव्यांशु आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

भीलवाड़ा सांसद अग्रवाल ने सदन में रखी भीलवाड़ा से मुम्बई प्रतिदिन रेल चलाने की मांग

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने संसद में रेलवे बजट पर चर्चा विषय पर बोलते हुए वस्त्रनगरी भीलवाड़ा से मुंबई के लिए रोजाना ट्रेन की माँग को सदन में पुरजोर तरीके से रखा।। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने संसद में रेलवे बजट पर चर्चा पर अपने प्रथम उध्बोधन में सदन के माध्यम से भीलवाड़ा की जनता का ह्रदय से धन्यवाद ज्ञापित किया उन्होंने अपना मत समर्थन देकर सदन में भीलवाड़ा की बात रखने का अवसर प्रदान किया।। सदन में अपनी बात रखते हुए अग्रवाल ने कहा भीलवाड़ा ओद्योगिकनगरी के नाम से विख्यात हैं यहाँ प्रतिमाह 10 हजार करोड़ मीटर कपड़ा उत्पादन होता है । व 50 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। सरकार को बड़ा रेवेन्यु प्रदाता है भीलवाड़ा। यहा से प्रतिदिन सैकड़ों उद्योगपति व्यवसायी विद्यार्थी व जनसाधारण मुम्बई के लिए यात्रा करते है। भीलवाड़ा की बहुप्रतीक्षित माँग को सांसद अग्रवाल ने पुरजोर तरीके से सदन में भीलवाड़ा में रेल सुविधाओं के विस्तार पर अपनी बात रख अपने इरादों को जाहिर कर दिया ।भीलवाड़ा से मुम्बई नियमित रेल सेवा प्रारंभ हो सके इसके लिए अजेमर से वाया भीलवाड़ा होकर चलने वाली रेल को प्रतिदिन चलाया जाए

जिला कलक्टर ने ली आपदा प्रबंधन की बैठक- बरसात से जलभराव के निस्तारण के लिए समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त करें अधिकारी

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तैयारियां सुदृढ़ करने के संबंध में सभी एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी फील्ड पर जाकर स्थिति का जायजा लें तथा आपदा की स्थिति में आमजन को तुरंत राहत सुनिश्चित करें।

जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए मड़पम्प व अन्य संसाधनों की हो तत्काल उपलब्धता

बैठक में निर्देश दिए गए कि ईमारतों के बेसमेन्ट, कोचिंग सस्थानों, शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक भवनों आदि में जल भराव की स्थिति न हो, यह सुनिश्चित किया जावें। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अंडरब्रिज, बस्तियों आदि में पानी भराव की स्थिति से निपटने के लिए मड़पम्प व अन्य संसाधनों की तत्काल घटनास्थल पर उपलब्धता के लिए निर्देशित किया गया। नगर निकायों के अधिकारियों को कचरा संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि गंदगी इकट्ठी न हों और आमजन को समस्या का सामना न करना पड़े। साथ ही सड़कों की मरम्मत, नालों की सफाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए।

जलभराव क्षेत्रों में आमजन विशेषकर बच्चों की आवाजाही पर रखें निगरानी

जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जलभराव वाले क्षेत्रों का आंकलन कर समुचित इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। इन जगहों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए साइन बोर्ड लगाए जाएं तथा आमजन विशेषकर बच्चों की आवाजाही की लगातार निगरानी की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि प्रार्थना सभा में बच्चों को बांध, तालाब आदि क्षेत्रों में ना जाने और नहाने से बचने के लिए जागरूक किया जाए।

पुराने एवं जर्जर भवनों का चिन्हीकरण करें

मेहता शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों व नगर परिषद ईओ को निर्देश दिए कि पुराने एवं जर्जर भवनों का चिन्हीकरण कर लें, साथ ही ऐसे भवनों को खाली कराने और वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति को समय से रोका जा सके। साथ ही अतिवृष्टि से प्रभावित आमजन को अस्थाई रूप से ठहराने के लिए स्कूल, धर्मशाला, सामुदायिक भवन की उपलब्धता के संबध में निर्देशित किया गया। बैठक में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि जिले के जुड़ का नाका (बिजौलिया), डामटी कोकडा (माण्डलगढ़), गोवटा बांध (माण्डलगढ़), जेतपुरा बांध (माण्डलगढ़) बांध 80 प्रतिशत या अधिक क्षमता तक भर चुके हैं। जिला कलक्टर ने इन क्षेत्रों में डाउनस्ट्रीम के गांवों में विशेष सावधानी के लिए एसडीएम को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को बारिश के मौसम में बांधों के जलस्तर की निगरानी, सफाई व्यवस्था, उचित यातायात प्रबंधन, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं सहित विभिन्न सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

पर्याप्त मेडिकल किट व जीवन रक्षक दवाईयां की उपलब्धता

मेहता ने बैठक में सीएमएचओ व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्याप्त मेडिकल किट व जीवन रक्षक दवाईयां की उपलब्धता, मोबाइल चिकित्सा दल की उपलब्धता व चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं। साथ ही बरसात के बाद गड्ढ़ों या अन्य स्थानों जहां-जहां पर भी पानी भरा रहता है, वहां कीटनाशक का छिड़काव एवं फोगिंग करवाने हेतु व्यवस्था की जावें।

मेहता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मीडिया में आ रही वर्षाजनित हादसों की खबरों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में धंसी सड़कों, टूटी नालियों के मरम्मतीकरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि आमजन को शीघ्र सहायता उपलब्ध हो सके।

नियंत्रण कक्ष 01482-232671

जिला स्तर पर बाढ़ व जल भराव सहित समस्याओं के निस्तारण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। आमजन अपने क्षेत्र से संबंधित जल भराव जैसी समस्याओं के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 01482-232671 पर सूचित कर सकते हैं।

मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 4-5 दिनों में भारी से अति भारी बारिश होने का पूवार्नुमान (ForecÔst) जारी किया हैं

जिला कलक्टर नमित मेहता ने जारी किए आदेश

द पुलिस पोस्ट

जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, अधिशाषी अधिकारी एवं समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी दिनांक 08 अगस्त 2024 तक मुख्यालय पर ही रहेंगें एवं अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगें। जिन अधिकारियों के पूर्व में अवकाश स्वीकृत हैं, उनके अवकाश तत्काल निरस्त किये जाते हैं।

MOST IMPORTANT OUT - TODAY
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
:: आदेश ::

नाबालिग लड़की को भगाने वाला दिल्ली से गिरफ्तार:पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर किया पीछा, किडनैप-पॉक्सो में मामला दर्ज

द पुलिस पोस्ट

अजमेर। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पड़ताल में जुटी है। कोतवाली थानाधिकारी वीरेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया- 22 जुलाई को पीड़िता के पिता ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किडनैप व पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी ब्यावर मसूदा अडवाणिया निवासी असलम काठात को दिल्ली से दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अजमेर शहर, ब्यावर के विभिन्न होटल, ढाबों के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी को 30 जुलाई को दिल्ली से दस्तयाब किया। पीड़िता को उसके परिजन के सुपुर्द करने के बाद गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

एक बार फिर बना दरबार मैदान में लगने वाला फेस्टिवल चर्चा का विषय

राजनीतिक व्यापारिक जगत पर हावी रही मुह पर राम बगल पर चुरी वाली बात बनकर रह गई

ऐसे भी इन नेताओ से कोरोना काल से परेशान थे अब और होना पड़ेगा

द पुलिस पोस्ट

3/6

शिवगंज- शहर में लगने वाले फेस्टिवल का शहर के व्यापारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने जब विरोध प्रदर्शन जाहिर किया तो उपखंड प्रशासन एवं पालिका प्रशासन द्वारा दी गई स्वीकृति को भी प्रशासन ने शहर की शांति को ध्यान में रखते हुए निरस्त किया । मेला लगने से शहर में बैठे व्यापारियों को जो मंदी के दौर में नुकसान होने की संभावना थी उसे देखते हुए एवं व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए पूर्व विधायक ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन से नियमानुसार कृषि भूमि पर दी गई स्वीकृति को निरस्त करने के लिए कहा जिसे लेकर प्रशासन ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए मेले की स्वीकृति को निरस्त किया लेकिन वही कुछ कथकित लेखनी के धनी ने अपने निजी स्वार्थ एवं विज्ञापन को ध्यान में रखते हुए शहर के व्यापारियों को दोषी ठहराते हुए एक बाहरी व्यक्ति जो आज यहां तो कल और कहीं उसकी पैरवी करते हुए । व्यापारियों को गलत बताता हुआ भ्रामक एवं मिस गाइड करने वाली पोर्टल पर खबरें वायरल कर अपने आप को बड़ा बताने लगा । वहीं शहर के व्यापारियों के मन में भी एक सवाल उत्पन्न हुआ क्या उसे व्यक्ति का आखिर उसे मेला व्यवसाय से ऐसा क्या संबंध था । क्या शहर में लगने वाले मेले फेस्टिवल पर ऐसे कलम के धनी को सहयोग करना उचित था। अपने विज्ञापन के चक्कर में एवं कुछ लाभ के चक्कर में शहर के व्यापारियों को गलत ठहराते हुए उसे व्यक्ति ने अपने ओहदे की गरिमा तक को भी खत्म कर दिया लेकिन लोगों को पता है की हकीकत क्या थी और सत्यता कहां तक थी जिसके चलते मेले पर प्रशासन ने स्वीकृति के बाद भी निरस्त का आदेश दिया । वहीं शहर के व्यापारियों एवं लोगों में एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है जहां यह बताया जा रहा है कि क्या उसे व्यक्ति की मिली भगत एवं नेताओं की नेतागिरी के चलते फिर व्यापारियों के साथ किया जाएगा बड़ा खिलवाड़ आखिरकार एसडीएम के आदेश को भी क्यों नहीं मान रहा दरबार मेगा ट्रेड फेयर मेला संचालक, एसडीएम के आदेश के बाद भी मेला व्यवसाय के द्वारा आज दिन तक ना तो टेंट खोले गए और ना ही महाराज मैदान की भूमि को खाली किया गया जो लोगों के अंदर एक बड़ी ही चर्चा का विषय है । व्यावसायिक उपयोग अगर कृषि भूमि पर होता है तो कानून रूप से वह सरासर गलत है जिसे देखते हुए प्रशासन के द्वारा इस मेले की स्वीकृति को निरस्त किया गया लेकिन वही फिर एक बार चर्चा का विषय यह सामने आ रहा है कि शहर में बीते कई वर्षों से लगने वाला बाबा रामदेव सेवा समिति के भंडारे के बहाने फिर एक बार मेला लगाने का मौका देख रहे कुछ पत्रकार, बाबा के भंडारे में बाबा के भक्तों के निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है जहां किसी प्रकार के धन लाभ का लेना-देना नहीं है हर कोई अपने द्वारा सेवा देता हुआ एवं तन मन से धन से जो भी सेवा होती है वह करता है उसके बावजूद भी शहर के लोगों से बात करने पर पता चला कि प्रशासन को धार्मिक आयोजन के लिए इस जगह को देने में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगानी चाहिए । धार्मिक आयोजन जहां बात धर्म के नाम पर आती है जहां पर किसी प्रकार के किसी व्यक्ति की भावना को आहत या ठेस नहीं पहुंचे ऐसा कार्य होता है तो उसके लिए प्रशासन को भी स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए आगे प्रशासनिक अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर करता है । व्यापारियों से बात करने पर पता चला कि शहर के महाराजा मैदान में चाहे वह कृषि भूमि है लेकिन नियम और अनुसंधान में लिखा गया है कि अगर कृषि भूमि पर किसी धार्मिक आयोजन को किया जाता है तो उसे पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं होती है कृषि भूमि पर अगर इसी तरह से वाणिज्यिक या व्यावसायिक उपयोग होता है तो उसे राजस्व को भी नुकसान होता है एवं वही वहां मौजूद धन व्यापारियों को भी इसका नुकसान का खामियां भुगतना पड़ता है । पूर्व विधायक ने पैरवी सही नही की अगर दिल से करते तो मैला नही होता क्या करे व्यापारी परेशान है किसके पास जाए जिसके पास जाते हैं वह राजनीतिक करते हैं ऐसे भी व्यापारी कोरोना काल से दुखी थे अब मेलो वालों ने और दुखी कर दिया स्वार्थी लोगों की वजह से शिवगंज शहर को पीछे की तरफ धकेल जा रहा है पर वर्तमान विधायक व मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे सिर्फ अपनी रोटी चेक रहे है जनता को रोना है बेचारा व्यापारी जाए तो जाए कहां

कोलोनी काटी रिको ने विकास किया पालिका ने

कोलोनी का साईड बैक व ओपन लैण्ड भूमि को बेचा गया है इसकी कारवाई क्यू नही हुई

पालिका प्रशासन ने ईस कोलोनी मे विकास नियमों के विरुद्ध किया अधिकारी से वसूला जाएँ

सधवी उधोग के मालिक के विरुद्ध कानुनी कारवाई करे नक्शे स्वीकृत मे सडक की भूमि को बेचा गया बगीचा बनाने की माँग

द पुलिस पोस्ट

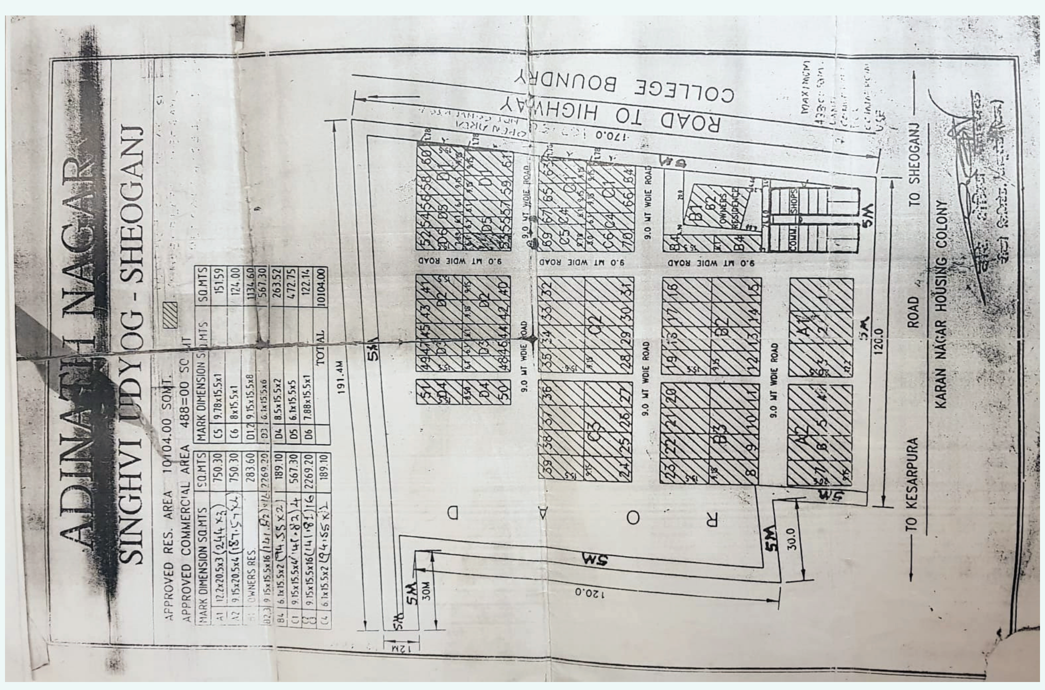

शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे तो आसपास में नगर पालिका का आवासीय क्षेत्र है उसी के बीच में एक टुकड़ा रीको का आया हुआ उसमें रिको आबूरोड द्वारा कालोनी काटी गई थी उस कॉलोनी में एक पार्टी द्वारा आम जनता को प्लाट बेचकर जनता के साथ बड़ा धोखा किया आदिनाथ नगर नाम से संघवी उद्योग के नाम से एक सेठ लोग ने लोगों को प्लाट बेचकर करोड़ों रुपए कमा कर चला गया लोगों को सुविधा के लिए जो जमीन दी थी वह भी इस पार्टी ने बेच दी इसी के पास सड़क की भूमि को भी इस सेठ में बेंच दी जो अब कुछ लोग इसमें प्लाट काट कर लोगों को गुमराह कर बेच रहे हैं रिको विभाग द्वारा इससे सेटिंग करके या धन लेकर इसकी रजिस्ट्री करवा दी क्योंकि इसकी रजिस्ट्री हो नहीं सकती थी इस प्लान के अंदर यह रोड की भूमि है वह ईस कॉलोनी की साइड बैक की भूमि पर भी लोगों ने कब्जा कर दिया इस कॉलोनी में जितनी भी भूमि छोड़ी गई उन सब में शिवगंज के सेठ लोगों ने कब्जा कर दिया और अंदर निवास करने वाले लोगों के लिए नहीं तो बगीचे के लिए छोड़ा और नहीं सड़क की भूमि शिवगंज के एक धन्ना सेठ ने इस पर जो कॉलोनी में साइड बैक 5 मीटर छोड़ा गया था जो करीब 15 फिट से अधिक बनता है वह उससे अधिक उस पर भी उन्होंने कब्जा करके मकान बना दिया सरकारी जमीन पर बड़ा बगीचा बनाकर लोगों को किराए पर दे रहे हैं और किराया खा रहे इस कॉलोनी के अंदर जितनी सड़क होनी चाहिए उतनी सड़क भी नहीं है और जो लास्ट में सड़क छोड़ी गई थी जो प्लान के अंदर भी आज रोड लिखा हुआ है उसको भी यह सेठ बेच कर खा गया जो इस कॉलोनी में खरीदने वाले लोगों के साथ धोखा किया इस सेठ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि इसने कॉलोनी काटने के बाद जो सुविधा होनी चाहिए वह रिकॉर्ड मे होनी चाहिए क्योंकि पैसा वाला सेठ ने लिया था पर इस कॉलोनी का विकास पालिका प्रशासन शिवगंज ने किया जो सरकारी आदेशों की धजिया उड़ा कर इन्होंने इस कॉलोनी के अंदर रोड लाइट पानी लाइन वह सड़क बनाई जो पालिका को करोड़ों रुपए का नुकसान किया यह पैसा इस कॉलोनी के मालिक से वसूल करना चाहिए क्योंकि यह सेठ लोग सरकारी प्रशासन को थोड़ा कुछ पैसा देकर सरकारी जमीन को खा जाते हैं क्योंकि यह जमीन खरीदने वाले शिवगंज के बड़े नेता शामिल है और रोड की जमीन पर पट्टा कैसे बन जाए यह उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग करती है शिवगंज की जनता व जनता के साथ धोखा कर यह लोग सुविधा की जमीन बेचकर खा रहे हैं इसका करोडों रुपए कमाए यह सब फजीर्वाडा करके इस कॉलोनी में जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं है इस जमीन पर बड़ा बगीचा बनना चाहिए वह बच्चों के लिए गार्डन जरूरी है अंदर झूले वगैरा लगने चाहिए जिससे बच्चे खेल सके और बुजुर्ग लोग शाम सुबह बगीचे में आकर बैठ सके वह इस कॉलोनी मलिक को क्या पड़ी करोड़ों रुपए मिल रहे हैं जो जमीन पड़ी है उसको बेचकर खा रहे हैं उद्योग विभाग वाले इनके साथ मिले हुए हैं इसलिए उल्टे सीधे काम कर रहे हैं नहीं तो कब का रुक जाता और जो सुविधा के लिए छोड़ी के जमीन उस पर सुविधा के लिए सड़क वह बगीचा बनाना आवश्यक होता है क्योंकि रीको प्रशासन नहीं चाहता कि इस कॉलोनी में लोगों को सुविधा मिले क्योंकि यह जमीन शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के अधीन है और नगर पालिका प्रशासन को भी इस मलिक के विरुद्ध कार्रवाई करवा कर जो भी जमीन है वह पालिका को देनी चाहिए या लेनी चाहिए वह इसके चारों तरफ जमीन पड़ी साइड बैक जो 5 मीटर से अधिक है जमीन खाली होनी चाहिए उस पर भी लोगों ने कब्जा कर दिया तुरंत यह 5 मिटर जमीन खाली करवानी चाहिए तब जाकर इस कॉलोनी के सड़क चौड़े हो जाएंगे वह लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी और जिस सेठ ने सरकारी जमीन को बेची है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए तब जाकर इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों को न्याय मिलेगा और बगीचा बनने से बच्चे को बुजुर्गों को वह महिलाओं के लिए बैठने की सुविधा हो जाएगी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इनका क्या कहना है शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के कोलेज के पास रिको विभाग ने एक वर्धमान कोलोनी निजी सेठ लोगो ने अपने फायदा लेने के लिए रिको और पालिका प्रशासन को गुमराह कर कोलोनी काटी गई कोलोनी की साईड बैक भूमि ओपन लैण्ड भूमि व रास्ते की भूमि भी ईस सेठ ने लोगो को बेच दी कोलोनी स्वीकृत भी औधोगिक रिको विभाग वालो ने की थी पर अब अंदर निवासियों के साथ धोखाधड़ी की है क्यू की लोगो के जीवन में सब सुविधा चाहिए पर रिको औधोगिक विभाग व सेठ ने मिलकर लोगो के साथ धोखाधड़ी की है पालिका प्रशासन ने रोड लाईट व सी सी सडक का निर्माण भी करोडों रुपए खर्च करके बनाएँ यह पैसा औधोगिक रिको विभाग वालो से या सेठ लोग से वसूला जाएँ अन्यथा पालिका प्रशासन अध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी कनिष्ट अभियन्ता से वसूला जाएँ जो लोगो के सुविधाओं के लिए छोडी जमीन को खुल्ला किया जाएँ तब आम लोगो के साथ धोखाधड़ी नही होगी साईड बैक भुमी 15 मिटर छोडी है जो लाखों फिट है ओपन लैण्ड पर सेठ ने कब्जा कर लिया है जो अतिक्रमण हटाया जाएँ

सीमा देवी माली पार्षद नगर पालिका शिवगंज

शिवगंज नगर पालिका क्षेत्र के कॉलेज रोड पर बची आदिनाथ नगर जो संघवी उद्योग के नाम से काटी गई थी कॉलोनी में पोल फैक्ट्री के नाम से थी उसमें इस संघवी उद्योग वाले ने कॉलोनी काटकर यहां के पर निवास करने वाले लोगों के साथ धोखा किया नहीं तो इस कॉलोनी में कोई सुविधा क्षेत्र नही छोडा गया नहीं इसको वह रिको व उद्योग विभाग वालो ने सड़क बनाई नहीं लाइट लगवाई और नहीं पानी की व्यवस्था की यह तो पालिका प्रशासन ने सभी व्यवस्था की जो पालिका प्रशासन का धन खर्च हुआ वह इस संघवी उद्योग वाले से यह धन वसूल करना चाहिए वह सडक की जमीन खाली करवा कर इसने जो भी सड़क की भूमि बेची है उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए सड़क की जमीन को वापस कॉलोनी वालों के लिए सुविधा क्षेत्र करना चाहिए तब जाकर कॉलोनी निवासियों को न्याय मिलेगा नहीं तो कॉलोनी निवासी ठगा महसूस करेंगे खुद को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए व सधवी उधोग के मालिक से पैसा वसूल किया जाए जैसाराम माली अध्यक्ष जवाई पर्यावरण एवं वन विकास समिति शिवगंज ईस रिको की कोलोनी की सडक की जमीन बेचने वालो के विरुद्ध कारवाई की करनी चाहिए व शिवगंज नगर पालिका प्रशासन को जो खाली पडी जमीन अपने कब्जे में लेकर सधवी उधोग के मालिक के विरुद्ध कानुनी कारवाई करनी चाहिए तब जाकर कोलोनी मे निवास करने वाले लोगो को न्याय मिलेगा व भूमाफियाओ व भष्ट्राचारीओ के विरुद्ध कारवाई करनी चाहिए कमलसिह चौहान समाजसेवी गौरक्षक शिवगंज

रामलाल हत्याकांड मामले में उच्च अधिकारियों से जानकारी छुपाने के मामले में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड

पुलिस लाइन लगाया,बजरी माफियाओ से सांठगांठ की आशंका?

रात्रि में अवैध खनन होने का कही बार थाने में आया फोन लेकिन उच्च अधिकारियों से छुपाई जानकारी।

द पुलिस पोस्ट

शाहपुरा@(किशन वैष्णव) क्षेत्र के फुलिया कलां में रविवार रामलाला लोधा हत्याकांड में लापरवाही बरतने के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कावंत ने फुलिया कलां थाने के 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कावंत ने बताया की रामलाल लोधा हत्याकांड के मामले में लापरवाही बरतने,समय पर पुलिस उच्च अधिकारियों को जानकारी नही देने तथा अधिकारियों से जानकारी छुपाने के मामले में कांस्टेबल राकेश कुमार,श्याम सुंदर,और गोविंद को निलंबित कर दिया गया है।पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कावंत ने बताया की हत्याकांड की रात्रि अवैध बजरी दोहन करने की शिकायत को लेकर थाने में कही बार फोन आए लेकिन इन्होंने उच्च अधिकारियों से इसकी जानकारी छिपाई।जिसके चलते तीनो पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच होने तक महिला पुलिस लाइन शाहपुरा लगाया गया।वही क्या बजरी माफिया से थी इनकी सांठगांठ,क्या फुलिया कलां थाने से और

भी पुलिसकर्मी पर गिर सकती है गाज खेर फिलहाल मामले की जांच जारी है।जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा।

5 इंच के करीब हुई बरसात! विद्यालयों में अवकाश घोषित

द पुलिस पोस्ट

बिजयनगर ब्यावर। बिजयनगर क्षेत्र मे शुक्रवार को शुरू हुई बारिश ने जहां एक तरफ जनजीवन अस्तव्यस्त कर दिया, तो दूसरी ओर लोगों को गर्मी से राहत मिली है।पिछले 48 घंटो मे लगभग 5 इंच(113 एमएम) के करीब बारिश दर्ज की जा चुकी है। बिजयनगर शहर व आसपास के इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी शाम से तेज व मूसलाधार बारिश हुई है। ब्यावर जिला कलक्टर उत्सव कौशल के निर्देश पर तेज बारिश के मद्देनजर शनिवार को कक्षा 1 से 12 तक राजकीय व गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। बारिश दिनभर धीरे और मूसलाधार बारिश का दौर दोपहर तक चलता रहा।शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश से शहर व आसपास के इलाकों में सड़कों व गलियों जलभराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। बापू बाजार महावीर भवन नृसिंह द्वारा रोड आदि के अलावा भी कई जगह सड़कों पर मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी नजर आई। कई इलाकों में सड़कों से पानी लोगों की दुकानों में घुस गया और लोगों को परेशानी उठनी पड़ी। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली और लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं तेज व मूसलाधार बारिश के चलते आसपास के गांवो के तालाब व नालों में भी जलस्तर बढ़ता देखा गया। आस-पास के क्षेत्र के किसानों ने तेज बारिश को लेकर खुशी जाहिर की है।

राहुल की जनगणना की मांग के परिणाम

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

आगा खान ने यह पिटीशन दी थी या ली गई थी, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे सही रूप से पकड़ लिया था। इसका तरीका उन्होंने 1910 की जनगणना में निकाला। उन्होंने हिंदू को आगे हिंदू, जनजाति और अछूत नाम से तीन हिस्सों में बांट दिया। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन ब्रिटिश नीति कामयाब रही और 1947 में देश विभाजित हो गया। अंग्रेजों के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने मांग की थी कि जनगणना जाति के आधार पर की जाए, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरु इसके पीछे छुपी भावना को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था।

इस प्रतिवेदन का अगला भाग चौंकाने वाला है, जिसमें आगा खान कहते हैं कि जब भारतीयों को किसी भी संस्थान में उनकी संख्या के बल पर हिस्सेदारी दी जाए तो मुसलमानों को हिस्सेदारी का आधार उनकी संख्या को न माना जाए, बल्कि यह आधार रखा जाए कि मुसलमानों ने ब्रिटिश साम्राज्य की कितनी सेवा की है। आज भी यह शक जाहिर किया जाता है कि आगा खान ने यह प्रतिवेदन स्वयं दिया था या फिर अंग्रेजों ने उसे ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। ब्रिटिश सरकार ने शायद तभी से देश को विभाजित करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। आगा खान की पिटीशन से वायसराय इतना तो समझ गए थे कि हिंदुओं की जनसंख्या कृत्रिम रूप से कम करने का अवसर है...

वर्ष 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के बाद जब ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को अपदस्थ कर भारत का शासन स्वयं संभाल लिया तो उसने 1880 में भारत में पहली बार जनगणना शुरू की। उस समय मरदमशुमारी के लिए हिंदू, मुसलमान और ईसाई के नाम से तीन कॉलम होते थे। सिख, बौद्ध, जैन, ईरानी (पारसी को ईरानी कहा जाता था) की गणना भी अलग होती थी। सन् 1900 तक जनगणना इसी हिसाब से चलती रही। इस जनगणना में ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा थी कि भारत में विभिन्न मजहबों के लोगों की संख्या कितनी है, यह जान लिया जाए ताकि आगे की रणनीति बनाने में आसानी रहे। अब तक भारत में विदेशी मूल के मजहबों को मानने वालों की संख्या भी अच्छी खासी हो गई थी। विदेशी मूल के तीन मजहब ही भारत में पैर पसार रहे थे। इस्लाम पंथ, एशिया पंथ और मसीही पंथ (क्रि यन)। तीनों का भारत में आगमन मोटे तौर पर आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ था। अरबों, तुर्कों व मुगलों के लंबे शासन काल में इस्लाम पंथ में मतांतरित हो जाने वाले भारतीयों की संख्या भी अब तक काफी हो गई थी। इस्लाम पंथ में मतांतरित भारतीयों के अतिरिक्त एटीएम, यानी विदेशी मूल के मुसलमान भी थे। उस समय ईसाइयों की गिनती तो इस देश में नाममात्र ही थी। केरल में कुछ सीरिआई ईसाई थे जिन्होंने कभी अपने देश में इस्लामी आक्रमणों से भाग कर इस देश में शरण ले रखी थी। इसी प्रकार यूरोपीय जातियों को भी भारत के कुछ हिस्सों पर राज करते हुए लगभग सौ साल हो ही गए थे। इसलिए ईसाई पंथ में मतांतरित भारतीयों की भी कुछ संख्या थी ही। कुछ एंग्लो इंडियन थे। लेकिन इनकी संख्या उस समय नि त ही उंगलियों पर गिनी जा सकती थी।

वर्ष 1900 की जनगणना में ईसाई केवल एक प्रतिशत थे और मुसलमान 21 फीसदी थे। मुसलमानों में विदेशी मूल के मुसलमान, देसी मुसलमान और शिया मजहब को मानने वाले भी शामिल थे। इन दोनों के अतिरिक्त शेष भारतीय हिंदू हैं। लेकिन यह भी साफ हो गया था कि ब्रिटिश सरकार ने इस जनगणना में हिंदू शब्द को भौगोलिक न मान कर उसे मजहब का द्योतक शब्द मान लिया था। लेकिन 1885 में कांग्रेस और 1905 में मुस्लिम लीग के गठन से देश में कहीं-कहीं कुछ निकायों में भारतीयों को हिस्सा देने के लिए कानून बनने शुरू हो गए थे। यह चयन मतदान द्वारा होता था। यह ठीक है कि मतदान का अधिकार कुछ गिने-चुने भारतीयों को ही दिया जाता था, लेकिन एक नई पद्धति की शुरूआत तो थी ही। 1909 के अधिनियम में तो विधानपालिकाओं में भी चुनाव द्वारा कुछ स्थान भारतीयों द्वारा भरे जाने थे। इसलिए 1910 की जनगणना से पहले मुसलमानों का एटीएम (अरब, तुर्क, मुगल) मूल का खेमा सक्रिय हो गया। उनकी चिंता थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस्लाम पंथी (जिसमें मुसलमान और शिया पंथी दोनों ही शामिल थे) व मसीही के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीयों को हिंदू स्वीकार लिया था। इसका अर्थ परोक्ष रूप से यही था कि हिंदू इस देश की भौगोलिक पहचान को ही इंगित करता है। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमान और मसीही समुदाय को तो इस भौगोलिक पहचान से अलग कर ही दिया था। लेकिन यदि हिंदू को भी खंडित किया जा सके तो भारत को मानसिक तौर पर घायल करना आसान हो सकता था। 1910 की गणना से पहले एटीएम और ब्रिटिश सरकार ने इस संबंधी पूरी रणनीति तैयार कर ली थी। उसकी शुरूआत आगा खान के ज्ञापन से होती है जो उसने जनगणना के बारे में सरकार को दिया था। लेकिन हिंदू के भौगोलिक आधार को आगे बांटने की जरूरत ब्रिटिश सरकार को क्यों हुई, इसकी चर्चा भीमराव अंबेडकर ने की है। उनका मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर मुसलमानों द्वारा आगा खान के नेतृत्व में 1909 में ब्रिटिश सरकार को दिए गए प्रतिवेदन में से मिलेगा।

यह मैमोरंडम आगा खान ने उस समय के वायसराय लार्ड मिंटो को दिया था। आगा खान ने इस प्रतिवेदन में लिखा था कि 1900 की जनगणना में मुसलमानों की संख्या 62 मिलियन है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 1/5 प्रतिशत से लेकर 1/4 प्रतिशत के बीच ठहरता है। आगा खान ने आगे कहा कि जनगणना में से असभ्य समुदाय के लोगों, जिन्हें छिटपुट मजहब और एनिमिस्ट के नाते दर्ज कर रखा है, को निकाल दिया जाए। दूसरे, उन लोगों को जिन्हें हिंदू मान लिया गया है, लेकिन वे हिंदू नहीं हैं, भी निकाल दिया जाए तो देश में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की संख्या का प्रतिशत और भी बढ़ जाएगा। अंबेडकर ने वह पूरा मैमोरंडम अपनी किताब अछूत कौन थे में दिया है। लेकिन इस प्रतिवेदन का अगला भाग चौंकाने वाला है, जिसमें आगा खान कहते हैं कि जब भारतीयों को किसी भी संस्थान में उनकी संख्या के बल पर हिस्सेदारी दी जाए तो मुसलमानों को हिस्सेदारी का आधार उनकी संख्या को न माना जाए, बल्कि यह आधार रखा जाए कि मुसलमानों ने ब्रिटिश साम्राज्य की कितनी सेवा की है। आज भी यह शक जाहिर किया जाता है कि आगा खान ने यह प्रतिवेदन स्वयं दिया था या फिर अंग्रेजों ने उसे ऐसा प्रतिवेदन देने के लिए कहा था। ब्रिटिश सरकार ने शायद तभी से देश को विभाजित करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। अंबेडकर ने प्रश्न को आगे और बढ़ाया है। एक बात तो स्पष्ट है कि आगा खान की पिटीशन से वायसराय इतना तो समझ गए थे कि प्रथमया, हिंदू को उसकी भौगोलिकता से काट कर मजहब से पहले ही जोड़ दिया गया है, अब कृत्रिम रूप से उसकी जनसंख्या कम करने का भी अवसर है।

आगा खान ने यह पिटीशन दी थी या ली गई थी, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उसे सही रूप से पकड़ लिया था। इसका तरीका उन्होंने 1910 की जनगणना में निकाला। उन्होंने हिंदू को आगे हिंदू, जनजाति और अछूत नाम से तीन हिस्सों में बांट दिया। उस समय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन ब्रिटिश नीति कामयाब रही और 1947 में देश विभाजित हो गया। अंग्रेजों के चले जाने के बाद कुछ लोगों ने मांग की थी कि जनगणना जाति के आधार पर की जाए, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरु इसके पीछे छुपी भावना को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया था। लेकिन आज नेहरु की हवेली पर जिन लोगों का कब्जा हो गया है, वे इटली के मैकियावली के सिद्धांतों पर चलते हुए किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वे आज 2024 में उसी नीति को फिर से जीवित करना चाहते हैं, जो ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी। राहुल गांधी सलाहकारों की दी हुई स्क्रिप्ट पढ? की बजाय यदि बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान सभा के अंतिम सत्र में दिया गया उनका भाषण पढ़ लें तो वे देश की ज्यादा सेवा करेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार है)

संपादकीय

जालसाजी की सजा

पूजा खेड़कर अब अफसर नहीं रहेंगी। यूपीएससी ने ट्रेनी पूजा का न केवल सिलेक्शन रद्द कर दिया है बल्कि वह भविष्य में भी किसी इम्तिहान में शामिल नहीं हो पाएंगी। उन पर उम्र, माता-पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलने, तय सीमा से अधिक बार सिविल सेवा में शामिल होने के आरोप हैं। पूजा को दस्तावज की जांच के बाद सीएसई-2022 के नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, उनके भी कोई जवाब नहीं मिले। पुणे में पूजा ट्रेनी अफसर थीं, उस दौरान वीआइपी नंबर वाली निजी ऑड़ी में लाल बत्ती व महाराष्ट्र सरकार की प्लेट भी लगवा ली। शिकायत के बाद वहां से उनका तबादला हो गया, इसी दरम्यान हुई जांच में कई खुलासे होते चले गए। इस मामले के बाद यूपीएससी ने पंद्रह हजार से ज्यादा रिकमेंडेट उम्मीदवारों के दस्तावेज को भी जांचा। पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर ने न केवल अपना नाम, बल्कि मां-बाप का नाम बार-बार बदल कर परीक्षा दी। नाम के साथ, हस्ताक्षर, ई-मेल आईड़ी, पता, मोबाइल नंबर व फर्जी दस्तावेज भी लगातार बदले। इसलिए पता नहीं चल पाया कि पूजा कुल कितनी बार इस महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल हुई। जिस ओबीसी कैटेगरी से होने का दावा उन्होंने किया उसके प्रमाणपत्र के लिए अभिभावकों की सालाना आमदनी आठ लाख से कम होनी चाहिए। पूजा के पिता अवकाशप्राप्त आईएएस हैं, उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनकी सालाना आमदनी 43 लाख रुपये व संपत्ति चालीस करोड़.की है। इस लिहाज से वह नॉन-क्रीमीलेयर कोटे का लाभ लेने की दोषी भी हैं। सत्रह करोड़. की संपत्ति की मालिक पूजा पेशे से ड़ॉक्टर हैं। तीन सालों में विभिन्न दस्तावेज में उनकी उम्र बस एक वर्ष ही बढ़ी। उनके कई विकलांगता प्रमाण-पत्र भी सामने आ चुके हैं और विभिन्न दस्तावेज में आधार कार्ड. की बजाय राशन-कार्ड. नत्थी है। यह मामला पेचीदा, धोखाधड़ी व जालसाजी का भी है। कानून व कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा फजीवाड़े. व जालसाजी से पूजा ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को धूमिल किया है। उन्हीं को नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया में शामिल तमाम लोगों को सख्त सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत भी न कर सके।

चिंतन-मनन

दूसरों के दुख से अपना दुख ज्यादा बेहतर

एक कहावत है राजा दुखी, प्रजा दुखी सुखिया का दुख दुना। कहने का अर्थ यह है कि संसार में जिसे देखो वह अपने को दुखी ही कहेगा। राजा का अपना दुख है, प्रजा का अपना और जिसे आप सुखी माने बैठें हैं उससे पूछ कर देंखेंगे तो वह भी अपने दुखों की पोटरी खोलकर अपनी व्यथा गाने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास यह विकल्प हो कि आप अपना दुख किसी और को देकर दूसरे का दुख खुद स्वीकार कर लें तब आप कहेंगे कि अपना ही दुख भला है। इस संदर्भ में एक कथा है कि किसी गांव में एक फकीर आये। उनकी विशेषता यह थी कि वे किसी की भी समस्या दूर कर देते थे। उनकी इस विशेषता के बारे जिसे भी पता चला, वह उनके पास दौड़ा आया। अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई और लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्या फकीर को बताने की जुगत भिड़ाने लगे। नतीजा यह हुआ कि हर कोई बोलने लगा। कोलाहल मच गया। फकीर ने सभी को चुप होने के लिए कहा। सभी लोग चुप हो गये तब फकीर ने कहा, मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा। आप सब लोग एक-एक कागज पर अपनी समस्या लिखकर लाएं और मुझे दे दें।

कुछ ही देर में कागजों का ढेर लग गया। फकीर ने कागजों को एक टोकरी में रखा और उसे सबके बीच में रख दिया। एक आदमी की तरफ इशारा करके फकीर मे कहा, यहां से शुरू करके सब बारी-बारी से आएंगे और एक-एक कागज उठा लें। ध्यान रहे किसी को अपना कागज नहीं उठाना है। लोग एक-एक कर आए कागज उठा-उठा कर अपनी-अपनी जगह बैठ गए। फकीर ने कहा, अब इस कागज में लिखी किसी दूसरे की समस्या पढ़ो। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा पर उसके बदले कागज पर लिखी समस्या तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या बड़ी है तो उसे दूर करवाकर कागज पर लिखी दूसरे की छोटी-सी समस्या अपना लो। चाहो तो आपस में कागज बदल लो। जब तय कर लो कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लोगे तो मेरे पास आ जाना।

लोगों ने जब अपने पास कागज पर लिखी समस्या पढी तो वे घबरा गए। लोग एक दूसरे से कागज बदल-बदल कर पढ़ रहे थे। हर बार उन्हें लगता कि उनकी समस्या तो जैसी है वैसी है, पर इस नई समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे। ...

आसान नहीं है 'विकसित भारत -2047'

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'विकसित भारत-2047' पर देश में हर जगह चर्चा हो रही है। चचाओं का केंद्र अगले कुछ वर्षों में 7 प्रतिशत सालाना से अधिक औसत आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना है। इस समय भारत और चीन की तुलना करना उपयोगी हो सकता है। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 1991 में दोनों देशों में कृषि में रोजगार का प्रतिशत आसपास ही था। चीन में यह 60 प्रतिशत तथा भारत में 63 प्रतिशत था, किंतु विश्व बैंक के अनुसार करीब 30 साल बाद चीन में यह तेजी से कम होकर 23 प्रतिशत रह गया, जो भारत के 44 प्रतिशत आंकड़े से बहुत कम है। इन 30 साल के भीतर चीन में लगभग 20 करोड़ कृषि श्रमिक उद्योग और सेवा क्षेत्रों में चले गए। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में भी काफी संख्या में श्रमिक खेती से बाहर चले गए मगर इसी दौरान कृषि में रोजगार पाने वालों की संख्या 3.5 करोड़ बढ़ गई।

भारत को मौजूदा निम्न-मध्यम आय स्तर से उच्च आय स्तर या उच्च मध्यम आय स्तर तक लाने के लिए जरूरी बदलाव पर भी सबका ध्यान केंद्रित है । यह बदलाव रोजगार के ढांचे में होना है, जिसके तहत कृषि क्षेत्र से जुड़ा रोजगार घटना चाहिए और उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का रोजगार उतना ही बढ़ना चाहिए। वैसे भारत 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की आकांक्षा रखता है और इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में कृषि रोजगार के प्रतिशत की बात करें तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) देशों में यह लगभग 5 प्रतिशत है जो भारत में कृषि में वर्तमान रोजगार के प्रतिशत का लगभग आठवां हिस्सा है।

उच्च-मध्यम आमदनी वाले देशों में भी कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी आज भारत की तुलना में केवल आधी है। विकसित देशों की श्रेणी में शामिल कृषि वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक जैसे न्यूजीलैंड या ब्राजील में भी कृषि में रोजगार की हिस्सेदारी केवल 6-8 प्रतिशत के भीतर है। अगर भारत को 2047 तक उच्च आमदनी वाले देश का दर्जा हासिल करना है या उच्च-मध्यम आय के स्तर तक पहुंचना है तो उसे कृषि से बड़ी संख्या में श्रमिक उद्योग और सेवा क्षेत्र की ओर भेजने होंगे। इससे भी ज्यादा नाटकीय मामला वियतनाम का है, जहां 1991 में रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत थी मगर 2021 में घटकर 29 फीसदी रह गई। इसका बड़ा कारण यह है कि चीन और वियतनाम में इन वर्षों के दौरान अधिक निर्भरता विनिर्माण में रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने वाली वृद्धि पर रही है।

भारत के मामले में 1991 और 2021 के आंकड़ों की तुलना में एक अहम बिंदु छुप जाता है। कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट और उद्योग तथा सेवाओं में वृद्धि मुख्य रूप से 1990-91 से 2014-15 के बीच यानी 25 वर्षों दौरान हुई। उसके बाद से विनिर्माण में वृद्धि की कई योजनाएं आने के बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है। संभवतः कोविड के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की वापसी की वजह से भी कृषि क्षेत्र से रोजगार स्थानांतरित होने की रफ्तार धीमी रही है।भारत में राज्यों के बीच अंतर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अहम मुद्दा यह है कि हम किस दर पर उद्योग और सेवा क्षेत्र में बेहतर रोजगार सृजन कर सकते हैं ताकि कामकाजी उम्र वाले लोगों की बढ़ती संख्या और कृषि क्षेत्र से आने वाले लोगों को इसमें खप सके। 2047 तक कामकाजी उम्र वाली आबादी (15 से 59 वर्ष) का आधिकारिक पूवानुर्मान लगाएं और मान लें कि काम ढूंढने वालों में करीब 65 प्रतिशत हिस्सेदारी इसी समूह की होगी तो हमारे पास रोजगार ढूंढने वाले करीब 12 करोड़ नए लोग होंगे।

इसके अलावा सबसे मुश्किल पूवानुर्मान कृषि क्षेत्र से निकलने वाले श्रम बल के दूसरे क्षेत्रों में स्थानांतरण के मूल्यांकन का स्तर है। अगर हम विकसित या उच्च आमदनी वाला देश बनना चाहते हैं तब कृषि क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा कम होकर 10 प्रतिशत के स्तर पर आना चाहिए। इसका मतलब है कि लगभग 15 करोड़ लोगों को कृषि क्षेत्र छोड़ना होगा। इस तरह उद्योग और सेवा क्षेत्रों में 27 करोड़ से अधिक नए रोजगार पैदा करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार ढूंढने वाली आबादी और कृषि क्षेत्र छोड़ने वाली अतिरिक्त आबादी इसमें खप सके। अगले 25 वर्षों में यह तादाद सालाना 1 करोड़ से अधिक नई उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की नौकरियां हैं। असली चुनौती यह है कि हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए एक ऐसी योजना चाहिए जो उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगार के बेहतर मौके तैयार करे, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां आज भी औसतन करीब 55 प्रतिशत लोग खेती में रोजगार पाते हैं। अगले 25 साल में देश में जितने भी नए कामगार बढ़ेंगे, उनमें से लगभग 90 प्रतिशत इन पांच राज्यों से होंगे।

- राकेश दुबे

केरल : तबाही की वजह तलाशनी होगी

प्रमोद भार्गव

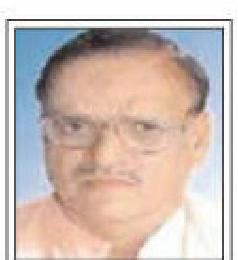

नयनाभिराम प्राकृतिक संपदा और बहुआयामी जल-संसाधनों के कारण केरल को उत्तराखंड की तरह भगवान का घर माना जाता है किंतु मूसलाधार बारिश और भूस्खलन हिमालय से लेकर केरल तक तबाही के कारण बन रहे हैं। सुदूर दक्षिण राज्य केरल में प्रकृति ने रौद्र रूप दिखाया और भूस्खलन एवं चेरियाल नदी के जलभराव क्षेत्र में बसे चाय बागान मजदूरों के चार गांवों ने मि ी के मलबे में जल समाधि ले ली। चेरियाल नदी पहाड़ों से निकलती हुई समतल भूमि पर चार दिनों से चल रही बारिश के कारण अत्यंत तेज गति से बही। इसी समय पहाड़ जल के प्रवाह से बह पड़े और पत्थरों व मलबे से चूरलमाला, अ ामाला, नूलपुझा और मुंडक्कई मलबे में पूरी तरह दब गए। जल की रफ्तार में हजारों पेड़, सैकड़ों वाहन भी जड़ों से उखड़ कर ग्रामों की ओर बहते चले आए। करीब 2200 की आबादी के 400 से ज्यादा घर कुछ पलों में मि ी के ढेर में बदल गए।

यह पूरा इलाका पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। केरल में केदारनाथ की तरह जो जल तांडव आया, उसने तय कर दिया है कि यह आपदा भगवान की देन न होकर मानव निर्मित है। पर्यावरणविद् ने भी इस बाढ़ को मानव निर्मित आपदा करार दिया है। कारण, बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई और पर्यटन में वृद्धि। चेरियाल बाढ़ क्षेत्र की जीवनदायिनी नदी मानी जाती रही है, लेकिन वही आधुनिक विकास के चलते मौत का सबब बन गई। कृषि प्रधान इस इलाके में चाय के अलावा नारियल, केला, मसाले और शुष्क मेवा की फसलें भी खूब होती हैं। पर्यटन भी राज्य की आमदनी व रोजगार का मुख्य स्त्रोत है। आय के ये सभी संसाधन प्राकृतिक हैं। गोया, प्रकृति का इस तरह से रूठ जाना आर्थिक रूप से खस्ताहाल केरल पर लंबे समय से भारी पड़ रहा है क्योंकि इसके पहले बरसात में ही केरल के 80 बांधों में से 36 बांधों के दरवाजे एकाएक खोल दिए गए थे। बांधों से निकले पानी ने बड़ी तबाही मचाई थी। यह तबाही पूरी तरह मानवीय भूल थी, लेकिन सिंचाई विभाग के किसी नौकरशाह की जवाबदेही तय करके दंड दिया गया हो, ऐसा देखने में नहीं आया।

केदारनाथ, अमरनाथ, हिमाचल और कश्मीर के जल प्रलय से हमने कोई सीख नहीं ली। गोया वहां रोज बादल फट रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ ढह रहे हैं। हिमाचल, असम और उत्तर प्रदेश में भी बारिश आफत बनी हुई है। बावजूद न तो हम शहरीकरण, औद्योगीकरण, तकनीकीकरण और तथाकथित आधुनिक विकास से जुड़ी नीतियां बदलने को तैयार हैं, और न ही ऐसे उपाय करने को प्रतिबद्ध हैं, जिनसे ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर न हो? शहरों में यह बढ़ती आबादी मुसीबत का पर्याय बन गई है। नतीजतन, प्राकृतिक आपदाएं भयावह होती जा रही हैं। सूरत, चेन्नई, बैंगलुरू, गुड़गांव ऐसे उदाहरण हैं, जो स्मार्ट सिटी होने के बावजूद बाढ़ की चपेट में रहे। यहां कई दिनों तक जनजीवन ठप रहा। बारिश का 90 प्रतिशत पानी तबाही मचाकर अपना खेल खेलता हुआ समुद्र में समा जाता है। यह संपत्ति की बरबादी तो करता ही है, खेतों की उपजाऊ मि ी भी बहाकर समुद्र में ले जाता है। देश हर तरह की तकनीक में पारंगत होने का दावा करता है, लेकिन जब हम बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, तो ज्यादातर लोग अपने बूते ही पानी में जान व सामान बचाते नजर आते हैं। आफत की बारिश के चलते डूब में आने वाले महानगर कुदरती प्रकोप के कठोर संकेत हैं, लेकिन हमारे नीति-नियंता हकीकत से आंखें चुराए हुए हैं। बाढ़ की यही स्थिति असम और बिहार जैसे राज्य भी हर साल झेलते हैं, यहां बाढ़ दशकों से आफत का पानी लाकर हजारों ग्रामों को डूबो देती है। इस लिहाज से शहरों और ग्रामों को कथित रूप से स्मार्ट व आदर्श बनाने से पहले इनमें ढांचागत सुधार के साथ ऐसे उपायों को मूर्त रूप देने की जरूरत है, जिससे ग्रामों से पलायन रु के और शहरों पर आबादी का दबाव न बढ़े ?

आफत की यह बारिश चेतावनी है कि हमारे नीति-नियंता, देश और समाज के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में दूरदृष्टि से काम नहीं ले रहे हैं। कृषि एवं आपदा प्रबंधन से जुड़ी संसदीय समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि जलवायु परिवर्तन से कई फसलों की पैदावार में कमी आ सकती है, लेकिन सोयाबीन, चना, मूंगफली, नारियल और आलू की पैदावार में बढ़त हो सकती है। हालांकि कृषि मंत्रालय का मानना है कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खेती की पद्धतियों को बदल दिया जाए तो अनेक फसलों की पैदावार में 10-40 फीसद बढ़ोतरी संभव है। बड़ते तापमान के चलते भारत ही नहीं, दुनिया में वर्षा चक्र में बदलाव के संकेत 2008 में ही मिल गए थे, बावजूद इस चेतावनी को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। बहरहाल, हर साल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकट नहीं झेलना पड़े, अतएव क्रांतिकारी पहल करना जरूरी हो गया है। वरना देश हर वर्ष किसी न किसी राज्य या महानगर में बाढ़ जैसी भीषण त्रासदी झेलते रहने को विवश होता रहेगा?

भष्ट्राचारी के विरुद्ध भष्ट्राचार ब्यूरो ने छापा मारा बडा धन व सम्पती मिलीं

योगेश आचार्य के विरुद्ध बडी कार्यवाही करीब दस जगह पर रेड सबसे बडा भष्ट्राचारी आचार्य ने सुमेरपुर नगर पालिका मे करोडों के भष्ट्राचार किया

विवेकानंद बस स्टैंड के सामने पहाडी की सरकारी जमीन की जाँच होनी चाहिए अपनों ने आपस मे बंटरबाट किया

ईसके साथ रहे पालिकाध्यक्ष व ठेकेदारों पार्षदो ने फायदा उठाया ईसके कार्यकाल की जाँच करावे

द पुलिस पोस्ट

सुमेरपुर नगर पालिका में जब से पालिका बनी तब से लेकर आज तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ जितना एक अधिशाषी अधिकारी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने यहाँ पर अधिशाषी अधिकारी रहे थे उसने अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया किसने पालिका धन डूबोने में कोई कमी नहीं रखी सरकारी जमीन जहाँ पड़ी थी वह कौड़ियों के भाव में देकर अपनी बड़े फार्म हाउस बनाने में पैसा लगा दिया किसने भ्रष्टाचार कर करोड़ों की संपत्ति बनाई जहां भी यह रहें वहां पर भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी चाहे बाड़मेर सिरोही तखतगढ भीनमाल सांचौर जालोर सहित जहां पर भी यह पोस्टिंग पर रहें वहां पर भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी क्योंकि सबसे भषट अधिकारी कहो या कर्मचारी कहो तो योगेश आचार्य ही रहा है इसके अलावा आज तक कोई कर्मचारी इतना भष्ट्राचारी नहीं होगा जितना योगेश आचार्य भ्रष्टाचार में लिफ्ट क्योंकि यह जिसनें करोड़ों रुपए के गबन किया फिर भी अधिकारियों ने इसको प्रमोशन पर प्रमोशन करते गए यह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था इसको अधिकारियों ने सम्मानित किया आयुक्त बनाया कमिश्नर बनाया उसकी की जांच भी अलग से हो रही है यह एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर अस्थाई नियुक्ति एलडीसी पद पर होते-होते हुए अधिशाषी अधिकारी कमिश्नर बाबू आयुक्त बनने में ऊपर तक कितना पैसा पहुंचा हुआ आप समझ जाओ यह जब तक जहां पर भी रहा चाय नगर परिषद हो नगर पालिका वहां की जांच करवाई जाए तो पता चल जाएगा की योगेश आचार्य ने कितनी सरकारी जमीनों को बेची वह कितना भ्रष्टाचार किया ईसने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बाड़मेर नगर पालिका में किया वह सुमेरपुर नगर पालिका में नगर परिषद सिरोही नगर परिषद जालौर तखतगढ नगरपालिका में करोड़ों रुपए के गबन घोटाले की उच्च अधिकारियों ने इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कई बार शासन सचिवालय में भेजे फिर भी इसके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि जब योगेश आचार्य को की सहायक अधिकारी सचिव नगर परिषद बाड़मेर पद रहते हुए इसको भष्ट्राचार अच्छा दिया था हरदेश शर्मा द्वारा 20-5-2022 को तब ईसने निदेशक शर्मा को लाखों रुपए का पैकेज पहुंचाया गया था किसने बदले में जितने भी बडे अधिकारी है उनको सेटिंग करके रखा था की कोई भी इसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होती थी अगर आपने इसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई का पत्र लिखा तो पत्र

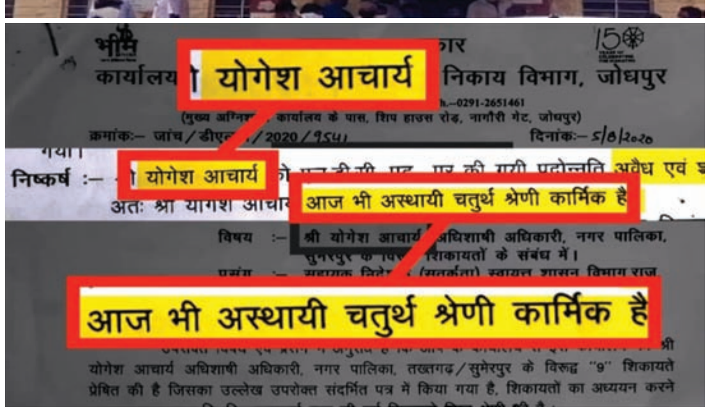

वहीं पर फीट हो जाता था क्योंकि इन्होंने जो भी वहाँ कर्मचारी है उनको मैनेज करके रखा था लोगों ने सैकड़ो बार शिकायत की फिर भी इसकी कोई कार्रवाई नहीं करना इसका मतलब भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रहा है उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर में एक बाबू जो शर्मा है उसके द्वारा ही इस पर इतनी मेहरबान है कि कोई भी गलत काम कर लो तो उसको माफ कर देता था क्योंकि उसके पास पैकेज पर पैकेज पहुंचे थे उसके घर पर जितने भी फर्नीचर परदे लगे हैं सब आचार्य द्वारा भेजे गए हदेश शर्मा का जो भी बांगला है वह उसके लिए पैसा अहमदाबाद जाता था आचार्य ने अहमदाबाद में पैसा पहुंचा गया पर कुछ नहीं हुई कारवाई क्योंकि जब भी देखो इसकी विरुद्ध कार्रवाई नहीं होकर उसका प्रमोशन दिया गया कई बार डी आर जोधपुर दलबीर सिंह गद्दा ने जांच के लिए लिखा पर उच्च अधिकारियों ने जांच नहीं कर उल्टा उसे प्रमोशन दिया गया क्योंकि यह भ्रष्टाचारी है इसने दलालों को भी मैनेज करके रखा है की कुछ भी कर लो पैसा दो इसको बाड़मेर जिला कलेक्टर व विधायक मेवालाल जैन एसपी साहब ने इसको स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का इसके विरुद्ध आज भी 14 से 15 मामले घोटाले के चलते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही भी जहां से रोकी हुई है अधिकारी कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है क्योंकि भ्रष्टाचारियों के पास धन पहुंचते ही भ्रष्टाचार रुक जाता है इसके सुमेरपुर कार्यकाल में जितने भी इतने पट्टे दिए निर्माण स्वीकृति दी बड़ी-बड़ी होटल बनाई काम्पलैक्स बने फार्म हाउस बने बड़ी-बड़ी कॉलोनी के प्लान

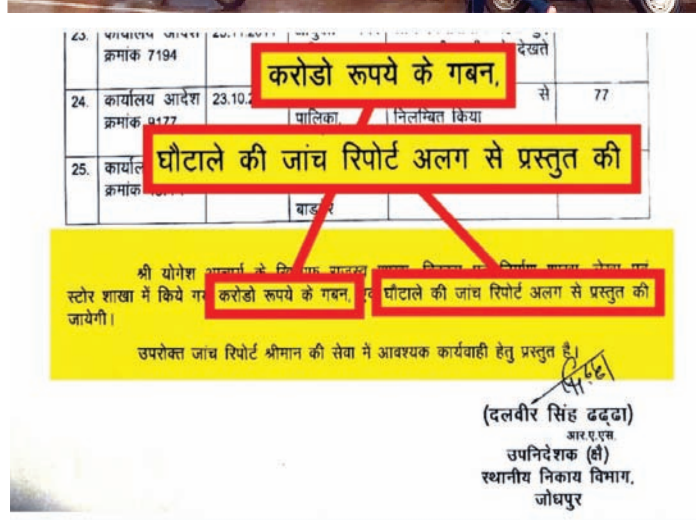

स्वीकृत हुए सब की जांच करवाई जाए तब पता चलेगा की योगेश आचार्य में भ्रष्टाचार कितना किया है योगेश आचार्य ने सुमेरपुर नगर पालिका वह सुमेरपुर नगर पालिका की जनता को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी इसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच करवाई जाए जो भी उसके साथ पालिका अध्यक्ष उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए इसमें पार्षदों को फोकट में दुकान दि क्यों अगर वह उसकी नीलामी होती तो करोड़ों रुपए आय पालिका प्रशासन की होती पर उसने आपस में बंटरबाट की बैठकर यह दुकान है यदि सरकारी संपत्ति को बेचने में इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी उसने नेशनल हाईवे पर प्लान स्वीकृत कर दिए जो नियमों के विपरीत नेशनल हाईवे के अनुसार सेन्टर से 200 फीट का प्रावधान है इसने कोई नहीं माना और प्लान स्वीकृत कर दिया इसने पेट्रोल पंप की स्वीकृति भ्रष्टाचार करके की फिर भी प्रशासन व उच्च अधिकारियों ने इसके विरुद्ध आज तक कारवाई नही की इसका मतलब यह हुआ सब तक मंथली पहुंच जाती थी यह भ्रष्टाचारी कई साल पहले पकड़ा जाता और जेल में होता तो स्वायत्त शासन विभाग की राजस्व की हानी नहीं होती इसने की सरकारी धन का दुरुपयोग किया होगा धन लुटने मे ईसने कोई कसर नहीं छोड़ी पालिका कोष को डूबने में अब इसके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए तभी पता चलेगा पर इसके साथ जितने भी भ्रष्टाचारी थे उन की भी जांच होनी चाहिए योगेश आचार्य सुमेरपुर नगर पालिका वह तगतगढ़ नगर पालिका इसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की जांच उच्च अधिकारियों से करवानी चाहिए और भ्रष्टाचार ब्यूरो को जांच होनी चाहिए तब जाकर ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई होगी आज जेल में जाएंगे इसके साथ पालिका अध्यक्ष सुमेरपुर व तखतगढ़ पार्षद दोनों जगह के पार्षदो ठेकेदारों को पालिका अध्यक्ष के परिवार का पार्षदों के परिवारों के ठेकेदार बनाकर जो पालिका की संपत्ति लुटी है उन सभी की जांच होनी चाहिए क्योंकि पार्षद अपने खून के रिश्ते को पालिका का ?1 का फायदा नहीं ले सकता पर इसमें कार्यकाल में करोड़ों रुपए की हेरा फेरी की है फर्जी पट्टे बनाएं और सैकड़ो काम ऐसे किया जिसकी जहां तुरंत खारिज करना चाहिए इसमें सुमेरपुर कार्यकाल में फर्जी कालोनियां स्वीकृत करवा दी व उसके पट्टे बनाकर दिए इसके नाम की जितनी भी जमीन है उन सभी जमीनों को जब्त कर सरकार को अपने नाम दर्ज करनी चाहिए वह जमीन है गरीबों के लिए आशियाने बना कर देना चाहिए जिससे गरीबों की दुआ मिलेगी सरकार को और भ्रष्टाचार्यों के भी बड़ी कार्रवाई होगी इसके परिवार में जितने भी इसके खास ठेकेदार बने हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए इसके मोबाइल डाटा के अनुसार उसकी भी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं चाहिए ऐसे भ्रष्टाचारियों की हुई तुरंत जाँच करनी चाहिए इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार ब्यूरो ने कार्यवाही की है उन सभी की जांच बराबर करके वह और उनके कारण होनी चाहिए पालिका में जितने भी कार्य किया है उनकी भी जांच करवाई जानी चाहिए सुमेरपुर तखतगढ़ सांचौर भीनमाल नगर पालिका व जालौर सिरोही बाड़मेर नगर परिषद में इसके कार्यकाल के वक्त की जांच उच्च अधिकारियों से करवाई जाए नहीं की किसी भ्रष्टाचारियों से नहीं तो इससे पैसा लेकर जांचों को प्रभावित कर लेंगे ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल से नहीं छोड़ा जाए क्योंकि भ्रष्टाचारियों पैसा देकर सब जांच प्रभावित कर सकते हैं

पालिका कॉम्प्लेक्स की मरम्मत की मांग को लेकर लोढा से मिले व्यापारी

काग्रेसी बोर्ड होने से नही होगी कारवाई ईसके भष्ट्राचार मे यही डुबे हुए है

ईस काम्पलैक्स के निमार्ण मे घोटाला हुआ था अब भी इसकी जाँच करवाई जाएँ

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज। शहर के धानमंडी क्षेत्र में वर्षो पूर्व पालिका प्रशासन की ओर से निर्मित करवाए गए पालिका कॉम्पलेक्स देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो रहा है। कॉम्पलेक्स की मरम्मत को लेकर व्यापारियों की ओर से कई बार पालिका प्रशासन से आग्रह किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर गुरुवार को व्यापारियों ने पूर्व विधायक लोढा से मुलाकात कर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करवा सहयोग का आग्रह किया। लोढा ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि कॉम्पलेक्स की मरम्मत करवाने में यथा संभव सहयोग किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पूर्व पालिकाध्यक्ष छगन गहलोत के कार्यकाल में पालिका प्रशासन की ओर से धानमंडी क्षेत्र में निर्मित करवाए गए पालिका कॉम्पलेक्स की दुकानों को पालिका ने निलामी के जरिए बेचा था। लेकिन इसकी छत पर पालिका प्रशासन का ही स्वामित्व था। लेकिन पालिका प्रशासन की ओर से देखरेख के अभाव में इस कॉम्पलेक्स की छत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात यह है कि दुकानों में बारिश के समय पानी गिर रहा है। जिससे उनका सामान खराब हो रहा है। इसके अलावा छज्जा भी क्षतिग्रस्त होने से वह कभी भी नीचे गिरकर बडे हादसे का कारण बन सकता है। कॉम्पलेक्स के जर्जरहाल को लेकर यहां दुकानों को संचालन करने वाले व्यापारी भी खौफजदा है। इस संबंध में व्यापारियों की ओर से कई बार लिखित रूप से आग्रह करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों में रोष है। इस संबंध में गुरुवार को व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व विधायक लोढा से उनके आवास पर मुलाकात कर उनको वस्तुस्थिति से अवगत करवाते हुए पालिका कॉम्पलेक्स की मरम्मत करवाने में सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। व्यापारियों की बात को सुन पूर्व विधायक ने पालिका के कनिष्ट अभियंता को फोन लगाकर व्यापारियों एवं आम नागरिकों के जान के जोखिम को देखते हुए तत्काल ही तकमीना बना मरम्मत करवाने के लिए कहा है। कनिष्ट अभियंता ने पूर्व विधायक को भरोसा दिलाया कि इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी वह जब ईस काम्पलैक्स की छत बिखरनी टूटनी चालु हुई तब कारवाई नही की अब पालिका मे बोर्ड काग्रेसी होने से जल्दी कारवाई करनी चाहिए पर राजनीतिक करनी आती है नेताओं को फोटो व अखबारो मे आने का शोक है थोथी राजनीतिक करते है कारवाई करवाओ नही तो कभी बडी जन होनी होगी तब कारवाई करोगे फिर कुछ नहीं होगा इस अवसर पर

विनोद कुमार, चंपालाल, ओमप्रकाश, सुरेश कुमार छीपा, रामाराम, पियुष माली, छोगाराम, मांगीलाल, राकेश माली, अय्युब खान, छगन लाल, मुकेश परमार, गिरधारीलाल, अजय कुमार, श्रवण कुमार, भबुतमल माली, दिपेश सोनी, दिनेश चौधरी, विवेक सेन, राकेश कुमार एवं जितेन्द्रसिंह राव मौजूद थे ईन काम्पलैक्स व्यापारिक संगठनों ने पालिकाध्यक्ष को विशेष अनुरोध है कि ईस काम्पलैक्स का रिपेयरिंग तुरंत करवाया जावे अन्यथा कभी बडा हादशा जनहानी होगी तब जिम्मेदारी कोन लेगा आपका कार्यकाल कुछ दिन ही बसे है इसलिए अपने हाथो से ईस काम्पलैक्स का रिपेयरिंग तुरंत करवाया जावे ।

राजकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में एस.डी.एम.सी. और महाविद्यालय विकास प्रबंधन समिति में सदस्यों का किया मनोनयन

पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष राठी का नाम भी शामिल हुआ बधाई देने वालो का ताता लगा

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज । भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शिवगंज के अध्यक्ष तारा राम कुमावत की अनुशंसा पर राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 1567 दिनांक 30.7. 24 के द्वारा ग्रामीण विकास पंचायत राज आपदा प्रबंधन संहिता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय में विकास प्रबंधन समिति के एस.डी.एम.सी. सदस्यों का मनोनयन कर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया की मनोंनयन सदस्यों का साला प्रधान व प्राचार्य को निर्देशित करने के निर्देश दिए। मंडल महामंत्री कुंदनमल राठी ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार राजकीय

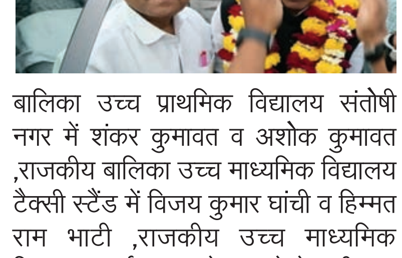

बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय संतोषी नगर में शंकर कुमावत व अशोक कुमावत ,राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टैक्सी स्टैंड में विजय कुमार घांची व हिम्मत राम भाटी ,राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आर्य समाज के सामने में मांगीलाल टॉक व दिनेश मीणा, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जगनाथ जी मंदिर के पास में लक्ष्मी नारायण गहलोत व परमेश कुमार, महात्मा गांधी विद्यालय न्यू गोकुलवादी में प्रकाश भाटी व मुकेश कुमार प्रजापत, एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादावाड़ी में शंकर लाल परिहार व मानक प्रजापत को मनोनीत सदस्य किया गया । इसी के साथ महाविद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति में गंगाराम गोयल व कुलदीप सिंह तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय में श्रीमती उषा अग्रवाल व तेज कंवर को विकास समिति के सदस्य मनोनीत किए गए।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, दो की मौत:पशुओं से भरी पिकअप का टायर फटा; पीछे से कैंटर ने मारी टक्कर

द पुलिस पोस्ट

दौसा। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुरुवार-शुक्रवार की रात 2.30 बजे पिकअप और कैंटर की भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप सवार दो लोगों की मौत हो गई। दो भैंसें भी मर गईं। जबकि एक युवक घायल हो गया। हादसा पिलर नंबर 212 के पास हुआ। राहुवास थाना प्रभारी रघुवीर सिंह ने बताया- देर रात सूचना मिली कि एक्सप्रेस हाईवे पर पशुओं से भरी पिकअप का टायर फट गया। इससे पिकअप अचानक रुक गई। इस दौरान पीछे से आ रही कैंटर ने पिकअप को टक्कर मारी दी। कैंटर की जोरदार टक्कर से पशुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में पिकअप ड्राइवर पिन्टू (35) पुत्र धारा सिंह बंजारा निवासी गोपीपुर थाना कोटपूतली की दबने से मौत हो गई। पिकअप सवार राजू बंजारा (25) पुत्र बहादुर बंजारा निवासी बनगोड़ी थाना पिलानी जिला झुंझुनू और शेरू बंजारा (19) पुत्र कैलाश बंजारा निवासी लवाणा सारदा तहसील गंगापुर गंभीर रूप से घायल हो गए। दों को आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस से दौसा के जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां सुबह इलाज के दौरान राजू बंजारा ने भी दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को जिला अस्पताल की मॉच्युर्री में रखवाया। शुक्रवार सुबह परिजनों के आने के बाद उनकी मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कर शव सौंपे गए। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद पुलिस ने एक्सप्रेस वे से क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड हटाकर यातायात को सुचारु करवाया गया। राहुवास थाने के ड्यूटी अधिकारी ने बताया- पिंटू और राजू पशुओं की खरीद-फरोख्त करते थे। वे तीसरे साथी शेरू के साथ गुरुवार को सवाई माधोपुर से दिल्ली पशु लेकर जा रहे थे। इस दौरान पिकअप का टायर फटने हादसा हो गया। पिकअप में भैंसें थीं। एक्सीडेंट में दो भैंसें भी मर गईं।

ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत भीलवाडा पुलिस की बड़ी कार्यवाही

विभिन्न थाना क्षेत्र से खोये हुए 124 मोबाईल बरामद कर उनके धारकों को लौटाये गये

500 से अधिक मोबाईल नंबर की सीडीआर व आई.एम.ई.आई का किया विश्लेषण

साईबर धोखाधडी के 02 प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया

बरामद मोबाईलों की अनुमानित कीमत 25 लाख रुपये।

05 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

58 संदिग्धों से पूछताछ कर अन्य थानों में वांछित होने से संबंधित थाने को सूचित किया।

द पुलिस पोस्ट

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा श्री राजन दुष्यंन्त ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.07.2024 से विशेष अभियान ह्यह्यऑपरेशन एंटी वायरसह्नह्न चलाया जा रहा है। उक्त ऑपरेशन के तहत गुम/चोरी हुए मोबाईल को बरामद कर उनके असली मालिकों को वापस दिलाने एवं गुम व चोरी हुए मोबाईल के माध्यम से धोखाधडी पर अंकुश लगाने एवं साईबर ठगी की वारदातों को ट्रैक कर ऐसे अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कर साईबर ठगी पर रोक लगाने का लक्ष्य रखा गया। जिसके तहत साईबर धोखाधडी के 02 प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। 05 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत पाबंद कराया गया। 58 संदिग्धों से पूछताछ कर अन्य थानों में वांछित होने से संबंधित थाने को सूचित किया।

श्री राजन दुष्यंन्त ने बताया कि जिले में गुमशदा मोबाईल के सम्बंध में सूचना देने के लिए सेंट्रल इक्यूपमेंट इर्डेन्टिटी रजिस्टर (उएक्रक्र) बनाया गया है। इस पोर्टल पर जिला में गुमशुदा मोबाईल के सबं ंध में सूचना प्रविष्ट की जाती है। पोर्टल का संचालन साइबर सेल द्वारा किया जाता है। साइबर सेल द्वारा समय समय पर प्राप्त मोबाईल गुमशुदगी की शिकायतो ं के आधार पर मोबाईल ढूढने का कार्य किया जाता हैं।

जिले में गुम हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए श्री विमल सिहं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय के सुपरविजन में जिला साइबर सेल की विशेष टीम गठित कर विभिन्न थानों में दर्ज की गई मोबाईल गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर 500 स ` अधिक मोबाईल नंबर की सीडीआर व आई.एम.ई.आई का किया विश्लेषण कर दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड आदि राज्यो ंसे कुल 124 मोबाइल बरामद किये गये। सर्वाधिक 30 मोबाईल प्रतापगनर थाना क्षेत्र द्वारा बरामद किये गये। बरामद मोबाईलों में मुख्यतः वीवो, रेडमी, ऑप्पों व एप्पल कम्पनी के मोबाइल हैं जिनका बाजार मूल्य लगभग 25 लाख रुपये है।

मोबाईल बरामदगी की उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में साइबर सेल में पदस्थापित आशीष कुमार स.उ.नि., दीपक जांगीड कानि. 858, अंकित यादव कानि. 1979, पिन्टू कुमार कानि 494, महेन्द्र कानि. 669 एवं छोटू लाल रेबारी कानि. 655 की विशेष भूमिका रही।

भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर

राजकीय व निजी चिकित्सा संस्थानों में ग्रीन लाईटिंग कर अंगदान के लिए फैलायी जाएगी जागरूकता

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, अंगदान कर जरूरतमंद व्यक्तियों को जीवनदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त के अवसर पर 2 व 3 अगस्त को दो दिवस तक जिले के राजकीय व निजी चिकित्सा संस्थानों आदि के भवनों पर सायंकाल ग्रीन लाईटिंग कर अंगदान करने के लिए जागरूकता फैलायी जाएगी। ये निर्देश शुक्रवार को राज्य स्तर से आयोजित अंगदान जागरूकता अभियान एवं राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान मिशन निदेशक, एनएचएम डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राज्य स्तर से आयोजित हुई वीसी के माध्यम से मेडिकल कॉलेजों के प्रतिनिधियों, चिकित्सा अधिकारियों सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये है।

कार्यक्रम के दौरान माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती शुभ्रा सिंह व मिशन निदेशक, एनएचएम डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी द्वारा प्रदेश के ऑर्गन डोनर्स परिजनों, अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने एवं उत्कृष्ठ कार्य करने वाले चिकित्सा विभाग के कार्मिकों, गैर सरकारी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। जिला स्तर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिका डॉ0 चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी, डीपीएम योगेश वैष्णव, डॉ0 सुरेश चौधरी सहित चिकित्सा विभाग के विभिन्न अनुभागों के अनुभाग अधिकारियों ने वीसी में भाग लिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि जिले में अंगदान के प्रति समाज में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जायेगा। भारतीय अंगदान दिवस के मौके पर 2 व 3 अगस्त को चिकित्सा संस्थानों के भवनों पर ग्रीन लाईटिंग कर अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाकर इस मुहिम को मिलकर आगे बढाया जायेगा। इसकों लेकर चिकित्सा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, समाज के प्रबुद्धजनों, जिला अस्पतालों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि आमजन को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही समन्वय स्थापित कर ट्रोमा सेन्टर, एम्बुलेंसकर्मियों सहित विभिन्न विभागों को इससे जोड़ा जाएगा ताकि जिले में अंगदान के प्रति जनचेतना जागृत की जा सके। भारतीय अंगदान दिवस के दौरान आमजन को जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक अंगदान की शपथ दिलवायी जाएगी एवं जो लोग अंगदान करना चाहते हैं उनसे सहमति ली जाएगी।

मौत से पहले होमगार्ड बोला करते हैं दादागिरी

भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कहा- अगर मर जाऊं तो विभाग जिम्मेदार

दौसा। दौसा शहर निवासी एक होमगार्ड सीताराम सैनी (48) की गुरुवार को तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। होमगार्ड का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इससे होमगार्ड विभाग में हडकंप मचा हुआ है। वीडियो एक माह पहले का बताया जा रहा है। इसमें वह अधिकारियों पर सुनवाई न करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। होमगार्ड सीताराम दौसा शहर में बाबाजी की छावनी इलाके का निवासी था। पिछले काफी समय से वह बीमार था। गुरुवार को उसे दौसा जिला हॉस्पिटल से जयपुर रेफर किया गया था। रास्ते में उसने दम तोड़ दिया था। एक महीने पहले दौसा के होमगार्ड ऑफिस में उसने वीडियो बनाकर कहा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार ऑफिस होगा।

वीडियो में होमगार्ड ने यह कहा

वीडियो में सीताराम सैनी नजर आ रहा है। उसने कहा- इस महीने में मेरा रोटेशन है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सुबह 9 बजे का आफिस में बैठा हुआ हूं, पूछता हूं तो मेरे पर दादागिरी करते हैं। 9 बजे से अब तक सवा बज गए। न तो साहब आए और न कोई और कार्मिक। होमगार्ड आफिस में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं मानसिक तनाव में हूं, मेरे साथ कोई घटना हो जाए तो होमगार्ड ऑफिस जिम्मेदार होगा। मैं पहले ही बीमार चल रहा हूं। अपने-अपने आदमी की ड्यूटी लगा देते हैं। पहले तो लिस्ट डालते थे, लेकिन अब वह भी नहीं डालते तो फिर ग्रुप का क्या मतलब हुआ भाई लोगों। जिसकी जहां इच्छा होती है, वहीं ड्यूटी लगा देते हैं। गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है। होमगार्ड आफिस में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि मैं मर जाऊं तो जिम्मेदार आफिस वाले होंगे, जय हिंद।

ड्यूटी नहीं मिलने से परेशान चल रहा था

होमगार्ड सीताराम रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं मिलने से परेशान बताया जा रहा था। इसे लेकर उसने अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 1 जुलाई को वह ऑफिस में अधिकारियों से मिलने गया तो वहां कोई नहीं मिला। इससे दुःखी होकर उसने वीडियो बनाकर कई आरोप लगाए। 2 जुलाई को उसे नोटिस जारी किया गया। उसने लिखित में मांफी मांग ली थी। लेकिन ड्यूटी नहीं लगाने से वह तनाव में था। पिछले सप्ताह उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर परिजनों ने इलाज कराया। गुरुवार 1 अगस्त को हालत गंभीर होने पर उसे दौसा जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया था। लेकिन सीताराम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

डिप्टी कमांडेंट बोले- आरोप निराधार, सीताराम बीमार था

मामले को लेकर डिप्टी कमांडेंट अमन रस्तोगी ने कहा- होमगार्ड सीताराम पहले जयपुर में तैनात था, स्वास्थ्य खराब होने के कारण दौसा में स्थानान्तरण करा लिया था। दौसा जिले में 417 कार्मिकों में से 308 की रोटेशन के अनुसार ड्यूटी लगती है।

राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर हिंसा:विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, अगस्त में होना है शिलान्यास

द पुलिस पोस्ट

बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में बन रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर शुक्रवार को स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। प्लांट के लिए जमीन खाली कराने गई पुलिस पर यहां रह रहे लोगों ने पथराव कर दिया। वहीं जवाब में पुलिस ने भी हाईवे जाम कर रही महिलाओं को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़े। करीब 3 घंटे चली हिंसा में पुलिस के 3 जवान और कुछ ग्रामीण घायल हो गए। पुलिस ने भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। विवाद के बाद पुलिस ने पावर प्लांट के लिए जमीन खाली करा ली है। अगस्त के आखिरी सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने आ रहे हैं। दरअसल, बांसवाड़ा के छोटी सरवन में 2800 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना है। यहां बाउंड्री वॉल बनाकर इसकी जद में आ रहे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों के विरोध को देखते हुए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पुलिस से मदद मांगी थी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों की पुलिस को मौके पर तैनात कर लोगों को हटाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

एक जवान का सिर फूटा

शिलान्यास की तारीख नजदीक आने के कारण इन परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा रहा था। जबकि स्थानीय लोग मांग पूरी होने तक हटने को तैयार नहीं थे। शुक्रवार सुबह जमीन पर जब एनपीसीआईएल ने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू किया तो लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। सुबह करीब 10:30 बजे बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध को बढ़ता देख पुलिस ने जब इन्हें हटाना शुरू किया तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में क्यूआरटी का जवान कल्पेश गरासिया घायल हो गया, जिसके सिर पर पत्थर लगा। उसे बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है।

महिलाओं ने जाम किया हाईवे, बीएपी नेता समेत कई लोग हिरासत में

इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय महिलाओं ने नेशनल हाईवे 927-अ (बांसवाड़ा-डूंगरपुर-रतलाम) हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने महिलाओं और लोगों को हटाने का प्रयास किया। इस पर वहां भगदड़ मच गई और कुछ लोग पहाड़ी पर चले गए और वहां से पथराव शुरू कर दिया।

इस मामले में कोतवाली पुलिस ने बीएपी नेता हेमंत राणा समेत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस पथराव में क्यूआरटी के जवान कल्पेश गरासिया के सिर में चोट लगी है। उनका अभी बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।

मांग पूरी होने से पहले शुरू हुआ विस्थापन, इसीलिए भड़के ग्रामीण

ग्रामीणों की मांगों को पूरा करने से पहले ही उनके विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो गई, इसीलिए वे भड़क गए। उनका कहना है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक विस्थापित नहीं होंगे।

6 गांवों के 3 हजार लोगों को किया जाना है विस्थापित

परमाणु बिजली घर का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इस क्षेत्र में आने वाले 6 गांवों बारी, सजवानिया, रेल, खड़िया देव, आडीभीत और कटुम्बी में रहने वाले करीब 3 हजार लोगों को विस्थापित किया जाना है।

इन परिवारों को सरकार द्वारा 415 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। इसके बदले में 553 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। इन गांवों से विस्थापित होने वाले लोगों के लिए पास के खड़िया देव में 60 हेक्टेयर जमीन मकान बनाने के लिए ढूंढी गई है।

18 जुलाई को मानगढ़ के प्रदर्शन में की थी पावर प्लांट रद्द करने की मांग

पिछले महीने 18 जुलाई को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर हजारों की संख्या में इकट् ?ठा हुए आदिवासियों ने सभा कर कई मुद्दे उठाए थे। इसमें भी उन्होंने छोटी सरवन में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को निरस्त करने की मांग की थी। इसी मांग को लेकर लोकसभा चुनाव का भी ग्रामीणों ने बहिष्कार किया था।

डर नाम की कोई चीज राहुल गांधी के अंदर नहीं : पप्पू यादव

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का चक्रव्यूह वाला बयान काफी चर्चा में है। अब राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा कि भाजपा के लोगों को उनका चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया और ईडी के लोगों ने उन्हें बताया है कि छापेमारी की योजना बन रही है। राहुल गांधी के पोस्ट पर बिहार की पूर्णिया सीट से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एक पॉकेट की संगठन बन चुकी है। यह पूंजीपति और उद्योगपतियों का संगठन है। ईडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शरद पवार के लिए अलग कानून है और अजित के लिए अलग। नीतीश कुमार के लिए पहले अलग कानून था, अब अलग हो गया है। चंद्रबाबू नायडू और जगन के लिए अलग कानून हो गया है। स्वाभाविक है कि राहुल गांधी विपक्ष की मजबूत आवाज हैं। उन्होंने ईडी की छापेमारी की बात कही है, तब इसका मतलब है कि उन्हें इसकी खबर है। राहुल गांधी हमेशा मरने के लिए तैयार रहते हैं। डर नाम की कोई चीज उनके अंदर नहीं है। उनके परिवार ने मौत को बेहद करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हजारों किमी बिना किसी सुरक्षा के जनता के बीच चलते हैं। इसलिए न ही उन्हें किसी संस्था से डर लगता है और न ही किसी व्यक्ति से। जो ईमानदार होता है उसे किसी चीज से डर नहीं लगता है। राहुल गांधी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।

राउ आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को राउ आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही हादसे की गंभीरता, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते फैसला लिया गया है। कुटुंब ट्रस्ट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की। दिल्ली के राउ आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इसके पहले कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाकर कहा था कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है, जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार कर दोषी को छोड़ देते हैं, तब यह दुख की बात है। अच्छा हुआ, आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी।

हिमाचल में संकट का दौर...आठ स्कूली बच्चे लापता , समेच गांव के 34 लोग लापता

शिमला । हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। शिमला, कुल्लू और मंडी जैसे तीन इलाकों में बादल फटने से कई लोगों की मौत हुई और हादसे में 50 लोग लापता हैं। अब समेज गांव के आठ स्कूली बच्चों के लापता होने की खबर है। लापता बच्चों में सात लड़किया और एक छात्र शामिल है। लापता हुए सभी छात्र बैडमिंटन और वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद ने कहा कि लापता छात्रों में 12वीं क्लास के हैं, 4 मैट्रिक और 6वीं और 9वीं कक्षा के एक-एक छात्र शामिल है। ये सभी छात्र स्थानीय निवासी थे। ये सभी बैडमिंटन और वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। प्राकृतिक आपदा से जुझ रहे हिमाचल में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 की रही। हालांकि, इसमें किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रामपुर के समेच गांव के 34 लोग लापता हैं, इसमें 18 महिलाएं शामिल हैं। वहीं, मंडी के रामबन गांव तक जाने वाले सभी रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। जगह जगह झरने बह रहे हैं। मलबा-कीचड़ और चट्टानें राहत और बचाव दलों को हर एक कदम पर चुनौती दे रहे हैं।

बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 12 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने किया मुआवजे का ऐलान

पटना। बिहार में भारी बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, बिहार के चार जिलों में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 12 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, गया में वज्रपात की चपेट में आकर पांच मौतें हुई हैं। जबकि जहानाबाद में 3 और नालंदा एवं रोहतास में दो-दो लोगों की जान गई है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, बिहार में 2 अगस्त को बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आकाशीय बिजली गिरने की घटना पर संवेदना व्यक्त की और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने लोगों से आपदा प्रबंधन विभाग की सलाह का पालन करने का भी आग्रह किया। फरवरी में राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत नवीनतम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2023-24) में कहा गया है कि राज्य में 2022 में बिजली गिरने से संबंधित 400 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा मौतें गया (46), भोजपुर (23), नवादा (21), बांका (21), औरंगाबाद (20) और नालंदा और कैमूर में 18-18 मौते हुई हैं। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि बिहार ने 2022-23 में आपदा प्रबंधन के लिए 430.92 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा, 285.22 करोड़ रुपये बिजली गिरने और डूबने जैसी स्थानीय आपदाओं के लिए समर्पित हैं।

छेड़छाड़ के आरोपी सेना के जवान को कोर्ट मार्शल ने किया बरी

नई दिल्ली। यहां की सैन्य अदालत ने एक अधिकारी की बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी जवान को बरी कर दिया है। आरोपी सिपाही सिग्नल कोर से है और उस अधिकारी से जुड़ा हुआ था। जो दिल्ली के एक नागरिक क्षेत्र में रह रहा था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अदालत ने पाया कि आरोपी सिग्नलमैन दोषी नहीं है। मामले का पीठासीन अधिकारी कर्नल रैंक का अधिकारी है और उनके द्वारा सुनाया गया फैसला अभी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की पुष्टि के अधीन है। अधिकारी की बेटी से कथित छेड़छाड़ का मामला 2019 में सामने आया था, जिसके बाद जवान को कोर्ट मार्शल ने 11 जुलाई को वह जवान 10 साल ज्यादा वक्त तक अधिकारी का सहायक रहा था। महिला द्वारा जवान पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ अगस्त 2019 में मामला शुरू हुआ था और 11 जुलाई को कोर्ट मार्शल ने अपना फैसला सुना दिया है। आर्मी कोर्ट ने फैसले का कारण बताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा उनके समक्ष पेश किए सबूतों पर सावधानीपूर्वक विचार और जांच करने बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में सक्षम नहीं है। वहीं, इस मामले में कथित घटना के तीन महीने बाद महिला ने आधिकारिक तौर पर सैनिक के खिलाफ आरोप लगाए थे, क्योंकि वह एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। सैनिक के वकील आनंद कुमार ने कहा कि यह मामला प्रशासनिक मुद्दों के कारण थोड़ा लंबा खिंच गया, लेकिन आखिरकार सैन्य अदालत से न्याय मिला है।

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड दान के जरिए से कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच कथित तौर पर लेन-देन की व्यवस्था की विशेष जांच दल द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती थी, और एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।

2027 तक 42 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य, भारत और जापान ट्रेड पर जयशंकर ने कहा

नई दिल्ली (एजेंसी) । सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज में 7वें जसजीत सिंह मेमोरियल लेक्चर में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि विश्व मामलों को आकार देने में बढ़ते राष्ट्रवाद की भूमिका को भी पहचाना जाना चाहिए। दुनिया के उन हिस्सों में जहां पुराना वैश्वीकरण मंत्र अभी भी प्रचलित है। सच्चाई यह है कि यह कई विकसित समाजों में निराशा को दर्शाता है जहां खराब भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विकल्पों के कारण जीवन की गुणवत्ता खराब हो गई है। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें लेकिन निकट भविष्य में दुनिया में राष्ट्रवादी काफी बढ़ जाएगा। यह जरूरी है कि भारत वैश्विक घटनाओं का मूल्यांकन करे और हमारे लिए राष्ट्रीय हित में जो अच्छा है उसकी गणना की जाए। ज्यादातर मामलों में जो भारत के लिए अच्छा है वह दुनिया के लिए भी अच्छा होता है। इसी के चलते ग्लोबल साउथ के साथ हमने मजबूत संबंध विकसित किया है और उन्होंने हम पर विश्वास जताया है।

पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि हम आज मानते हैं कि हमारे इतिहास को देखते हुए, पड़ोसियों के आकार को देखते हुए, हमारे पड़ोसियों और हमारे समाजशास्त्र को देखते हुए, इन रिश्तों को संभालना आसान नहीं है। भारत के बारे में हमारे कई पड़ोसियों की भावनाओं में राजनीतिक उतार-चढ़ाव होंगे। ये ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें हमें समय-समय पर स्वीकार करना होगा। हमारे कुछ पड़ोसियों में ऐसे अवसर आए हैं जब हम राजनीतिक बन गए हैं मुद्दा यह है कि हम वास्तव में कुछ बहुत गंभीर स्थितियों को कम करने में कामयाब रहे हैं... हमारे पड़ोस में, हमने दिखाया है कि हमारे पास खड़े होने, अपने हितों को आगे बढ़ाने, अन्य देशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है, और अक्सर मैं कहूंगा- उन्हें संसाधन दें और निश्चित रूप से उनसे बेहतर प्रदर्शन करें, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा रिकॉर्ड बहुत ठोस है।

एस जयशंकर ने कहा कि मैं सहमत हूं कि जापान के साथ व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश है। हमारा लक्ष्य 2027 तक 5 ट्रिलियन येन है। हम लक्ष्य के आधे रास्ते पर हैं। भू-अर्थशास्त्र में बदलाव के साथ, हमें जापान के साथ अधिक मेहनत करनी होगी... जापान के रणनीतिक लोग भी समझते हैं कि उन्हें भारत के साथ काम करना है और हमारे हित बहुत समान हैं।

मणिपुर में जागी शांति की उम्मीद... मेइती और हमार समुदाय के बीच सहमति

नई दिल्ली । मणिपुर के हालात सामान्य होने का इंतजार पूरा देश कर रहा है। वहीं राज्य और केंद्र भी तमाम उपायों के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। यह कोशिशें रंग लाईं जब मेइती और हमार समुदायों के प्रतिनिधियों ने मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले में शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास करने पर सहमति जाहिर की। एक जिले में शांति पर बात बनना कोई कम उपलब्धि नहीं है। इसलिए देश को उम्मीद है कि जिरीबाम जिले में शांति स्थापित होने के बाद पूरे राज्य में भी शांति और समृद्धि आएगी। बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि असम के कछार में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक प्रतिष्ठान में हुई बैठक में दोनों पक्षों के बीच यह समझौता हुआ। बैठक का संचालन जिरीबाम जिला प्रशासन, असम राइफल्स और सीआरपीएफ ने किया। बैठक में जिरीबाम जिले के थाडौ, पैते और मिजो समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के बाद इन समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया, ''बैठक में यह संकल्प लिया गया कि दोनों पक्ष सामान्य स्थिति बहाल करने तथा आगजनी और गोलीबारी की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास होगा। दोनों पक्ष जिरीबाम जिले में कार्यरत सभी सुरक्षा बलों को पूर्ण सहयोग देने वाले है। बताया जा रहा है कि अगली बैठक 15 अगस्त को होगी।

वायनाड हादसा- गांव और जंगलों में मिल रहीं लाशें, अब तक 308 की हुई मौत

वायनाड (एजेंसी) । वायनाड में हुए भूस्खलन हादसे में अब तक 308 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में गांव और जंगलों से लाशे मिल रहीं हैं। यहां युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कर चल रहा है। रेस्क्यू में जुटे बचावकर्मियों को अब तक 195 शव ही मिले हैं। बाकी, लोगों की मौत की पुष्टि उनके बॉडी पार्ट्स से की गई है। यानी 105 लोगों के शव का कोई ना कोई हिस्सा बरामद हुआ है, जिससे उनकी मौत कंफर्म हुई है।

सेना ने हादसे के बाद जो बेली ब्रिज बनाया है, इससे 25 एंबुलेंस मुंडकई पहुंचाई जाएंगी। मिट्टी में दबे शवों का पता लगाने के लिए दिल्ली से ड्रोन आधारित रडार शनिवार को आने वाला है। तलाशी अभियान में 6 कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। आज तमिलनाडु से 4 और कुत्ते लाए जाएंगे। 40 टीमें लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को प्रभावी बनाने के लिए सर्च क्षेत्र को 6 अलग-अलग भागों में बांटने की बात चल रही है। इनमें से पहला क्षेत्र अट्टामाला और आरणमाला से बना है। दूसरा क्षेत्र मुंडकई, तीसरा क्षेत्र पुंजरीमट्टम, चौथा क्षेत्र वेल्लरमाला विलेज रोड, पांचवां क्षेत्र जीवीएचएसएस वेल्लरमाला और छठा इलाका नदी का बहाव क्षेत्र है। हर टीम के साथ तीन स्थानीय लोग और एक वन विभाग का कर्मचारी भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा चलियार नदी के आसपास के 8 पुलिस स्टेशनों के

पुलिसवाले और तैराकी में माहिर लोग भी खोज करने जा रहे हैं। इसके अलावा हेलिकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा जा रहा है। तटरक्षक और नौसेना के साथ वन विभाग के कर्मचारी उन जगहों पर भी खोज करने जा रहे हैं, जहां शवों के बहकर आने की संभावना है। बता दें कि वायनाड में पहली लैंडस्लाइड 30 जुलाई की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह करीब 4.10 बजे फिर एक बार लैंडस्लाइड हुई। इसके साथ ही तीसरी बार फिर लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड में वायनाड के 4 गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गए, जिनमें से लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति के साथ मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

राज्यपाल सम्मेलन: एक समृद्ध अनुभव होगा और कामकाज में मदद मिलेगी : राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली (एजेंसी)। । दिल्ली में शुकवार से शुरू हुई दो दिनी राज्यपाल कांफ्रेंस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपालों को संबोधित किया। सम्मेलन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सम्मेलन का विचार-विमर्श प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा और उन्हें अपने कामकाज में मदद मिलेगी। मुर्मू ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबों और वंचित वर्गों के विकास, युवा विकास, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक खेती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

इस कार्यक्रम में केंद्र द्वारा तय एजेंडे पर किए गए काम की समीक्षा होगी। एमपी के विधानसभा चुनाव के पहले राज्यपालों की भूमिका में बदलाव कर केंद्र ने अंतर्राज्यीय मुद्दों को लेकर हर राज्यपाल को पड़ोसी राज्य के साथ बैठक करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों के साथ बैठक भी की है। बैठक में एमपी के सीमावर्ती जिलों और दूसरे राज्यों के एमपी से सटे सीमावर्ती जिलों की समस्याओं, बड़ी परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई थी।

अब दिल्ली में हो रही राज्यपाल कांफ्रेंस में इन मसलों पर केंद्र की ओर से रिपोर्ट ली जाएगी और अब तक की गई बैठकों की समीक्षा भी की जाएगी। राज्यपाल के दिल्ली प्रवास और दिल्ली में होने वाली बैठक के मद्देनजर राज्य सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर विभाग से संबंधित अपडेट जानकारी राज्यपाल को सौंपी है।

इस दो दिनी कांफ्रेंस के पहले 10 राज्यों के राज्यपाल बदले हैं या उनके राज्य बदले गए हैं। राजभवन सूत्रों के अनुसार राज्यपालों की भूमिका में बदलाव समय के साथ हुआ है। इस कारण कांफ्रेंस में राष्ट्रपति मुर्मू राज्यपालों को कुछ और जिम्मेदारी भरे काम सौंप सकती हैं।

अयोध्या में उस बच्ची से मिल आओ राहुल और अखिलेश... जिससे गैंगरेप तुम्हारे नेता ने किया : आचार्य कृष्णम

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भड़क गए हैं। उन्होंने पोस्ट के द्वारा उसमें कुछ तीखे सवाल पूछे हैं। आचार्य कृष्णम ने कहा कि अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप हुआ। बच्ची से मिलने के लिए अयोध्या चले जाओ। उस बच्ची से मिलने अयोध्या चले जाओ, जिसके साथ गैंग-रेप तुम्हारी पार्टी नेता ने ही किया है। कांग्रेसी नेता ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी टैग किया। उन्होंने कहा, सेक्युलरिज्म मौन है, ये मोईन खान कौन है।

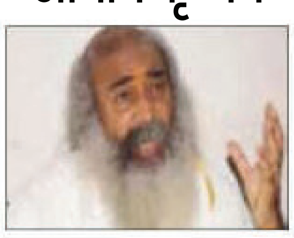

दरअसल अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी से पूछा कि अब तक मामले में जो आरोपी मोईन खान हैं, उसके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आरोपी का अयोध्या सांसद के साथ नजदीकी रिश्ता है। सपा नेता मोईन खान पर 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोप है। बच्ची के साथ आरोपी के नौकर ने भी बलात्कार किया। आरोपी का मन नहीं भरा तब बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर वायरल की धमकी देकर बच्ची के साथ कई बार गैंगरेप किया गया। इस घटना की जानकारी सबके सामने तब आई जब बच्ची गर्भवती हो गई और उसने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई। मां ने बेटी के साथ स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दी। हालांकि, पुलिस ने शुरुआती तौर पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन, जब हिन्दू संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाया तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

घुसपैठ रोकना सिर्फ केंद्र की नहीं, सभी की जिम्मेदारी : मुख्यमंत्री हिमंत

दिसपुर (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि घुसपैठ रोकना केवल केंद्र सरकार की नहीं बल्कि सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी से वह ''फॉर्मूला'' भी जानना चाहा कि ''अपनी जाति बताए बिना जाति सर्वेक्षण कैसे किया जाए।'' भाजपा के झारखंड चुनाव सह-प्रभारी शर्मा ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''झारखंड का संथाल परगना घुसपैठ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पिछले 20 वर्षों में इस क्षेत्र के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में घुसपैठियों की आबादी 50-60 प्रतिशत बढ़ गई है और स्थिति असम जैसी हो सकती है।''

उन्होंने दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी 1952 के 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 40-42 प्रतिशत हो गई है, जिसका मुख्य कारण घुसपैठ है। शर्मा ने कहा, ''अगर घुसपैठ जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब मुख्यमंत्री को उनके (घुसपैठियों के) सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राज्य को बचाना सभी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर आम सहमति बनानी चाहिए और घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।'' झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घुसपैठ के लिए बार-बार केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि इसे रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जातीय सर्वेक्षण तो चाहते हैं लेकिन अपनी खुद की जाति का खुलासा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा,'' जातीय सर्वेक्षण बिहार में कराया गया है। क्या यह सारे देश में कराया जाएगा या नहीं, यह एक अलग मामला है।

केदारनाथ में फंसे शिवपुरी जिले के श्रद्धालुओं से सिंधिया ने की बात

शिवपुरी । केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा के कारण मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के श्रद्धालु फंस गए। कइयों को सुरक्षित निकालने के बाद शेष लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन श्रद्धालुओं से बात कर उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सुबह केदारनाथ में बादल फटने के कारण वहां फंसे हुए श्रद्धालुओं से बात की। उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र गुना-शिवपुरी के श्रद्धालुओं के समूह के केदारनाथ में फंसने की सूचना मिली थी। केंद्रीय मंत्री ने इस सूचना पर एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर बचाव कार्यक्रम के माध्यम से बदरवास के लोगों को जल्द नीचे लाने का आग्रह किया था।

दस साल से भारत में रह रहे शरणार्थी को कोर्ट ने फटकारा कहा- उदारता का फायदा मत उठाओ

नई दिल्ली (एजेंसी)। यमन का शख्स बीते दस सालों में पुणे में रहा रहा है। अब भारत छोड़ने को तैयार नहीं है। अवधि से ज्यादा समय तक ठहरे एक शरणार्थी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इतना ही नहीं अदालत ने यमन के शख्स को पड़ोस में पाकिस्तान या किसी खाड़ी देश में जाने तक की सलाह दे दी। हाल ही में पुणे पुलिस की तरफ से उसे लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 10 सालों से भारत में रह रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच कर रही थी।

रिपोर्ट के अनुसार, जजों ने कहा, आप पाकिस्तान जा सकते हैं, जो पड़ोस में ही है। या आप किसी भी खाड़ी देश में जा सकते हैं। भारत के उदार रवैये का गलत फायदा न उठाएं। यमन के नागरिक खालिद गोमेई मोहम्मद हसन भारत में तय अवधि से ज्यादा रह रहे थे और उन्होंने पुलिस की तरफ से जारी नोटिस को भी कोर्ट में चुनौती दी थी।

वहीं दूसरी तरफ पुणे पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश हुए संदेश पाटिल की इस बात से कोर्ट सहमत था कि याचिकाकर्ता रिफ्यूजी कार्ड धारकों को अनुमति देने वाले 129 अन्य देशों में जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हम आपको सिर्फ 15 दिनों तक सुरक्षा दे सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं। इस दौरान कोर्ट ने कपल की बेटी की नागरिकता का भी मुद्दा उठाया, जिसका जन्म भारत में हुआ था। कोर्ट ने वकील से इस संबंध में सवाल किया। पाटिल ने कहा, मिलॉर्ड, अगर कोई पैरेंट भारतीय है, तो जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यहां दोनों यमन से हैं। साथ ही बच्ची का जन्म माता-पिता का वीजा खत्म होने के बाद हुआ है, जिसका मतलब है कि पैरेंट्स अवैध प्रवासी हैं। ऐसे में बच्ची को नागरिकता नहीं दी जा सकती।

बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता कुछ राहत चाहता था, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। हसन शरणार्थी कार्ड धारक हैं और उन्होंने जबरन डिपोर्ट किए जाने से बचने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में हसन ने कहा कि यमन सबसे खराब मानवीय संकट से गुजर रहा है और इसलिए वह भारत में बीते 10 सालों से रह रहा है। उन्होंने याचिका में कहा कि 45 लाख नागरिक विस्थापित हो गए हैं। हसन मार्च 2014 में स्टूडेंट वीजा पर भारत आए थे और 2015 में मेडिकल वीजा पर उनकी पत्नी भारत पहुंची थीं। हसन का वीजा फरवरी 2017 में खत्म हो गया और पत्नी का वीजा सितंबर 2015 में एक्सपायर हो गया था। पुणे पुलिस की तरफ से इस साल फरवरी में उन्हें लीव इंडिया

नोटिस जारी हुआ था और बाद में अप्रैल में भी नोटिस दिया गया था। पुलिस ने नोटिस मिलने के 14 दिनों में भारत छोड़ने के लिए कहा था। बेंच के सामने याचिकाकर्ता ने कम से कम ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिलने तक डिपोर्टेशन से सुरक्षा की मांग की थी।

द पुलिस पोस्ट की खबर का हुआ जोरदार असर

द पुलिस पोस्ट की खबर हुई सच साबित,डीएलबी निदेशक के पीए पर कसा एसीबी का शिकंजा,निकला करोडों का मालिक

भीलवाड़ा यूआईटी और नगर परिषद के मामले में कहां गई सीएम और पीएम की जीरो टॉलरेंस नीति..??

क्यों आंखें मूंदे है सरकार...भ्रष्टाचार पर कब होंगे यूआईटी में प्रतिस्थापित रहे बड़े आला अधिकारी भू कारोबारी,भू माफिया सफेद पोश राजनीतिक संरक्षण प्राप्त दलाल वह अकूक संपति के मालिक कार्मिक अफसर कब होंगे बेनकाब

द पुलिस पोस्ट

द पुलिस पोस्ट समाचार पत्र ने करीब 2 साल पहले सितंबर 2022 में अपने संस्करण में खबर प्रकाशित कर अवगत कराया था कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर में निदेशक के निजी सहायक विमलेश शर्मा ने 35 सालों से एक ही विभाग और एक ही सीट पर जमे रहकर करोडों रुपए के काले साम्राज्य को खड़ा कर लिया । इस समाचार पत्र ने यह भी बताया था कि किस प्रकार विमलेश शर्मा ने कई लग्जरी गाड़ियां, प्लॉट ,बैंक बैलेंस, आलीशान मकान और एयर कंडीशनर युक्त महल जैसा दिखने वाला घर बनाया हुआ है जिसकी कीमत भी करीब 10 करोड रुपए है । समाचार पत्र ने यह भी बताया था कि किस प्रकार अपने बेटे को इसी विभाग में मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लगवाया गया। करीब 2 साल बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में विमलेश शर्मा के ठिकानों पर दबिश में यह पाया कि शर्मा ने अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं।

स्वायत्त शासन निदेशालय का कर्मचारी करोड़पति
बेटा-बहू को लगाया विभाग में, योग्यता नहीं होते हुए भी बेटी को बनवाया सरकारी वकील
खबर का हुआ असर

द पुलिस पोस्ट
THE POLICE POST
निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग का निजी सचिव बना करोड़ों का मालिक
खबर का हुआ असर

यूआईडी के घोटाले के जांच की मांग जिला प्रभारी की मीटिंग में उठी मांग
स्थानीय संवाददाता पंकज गर्ग ने प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग
यूआईटी में लंबे समय से हो रहे भ्रष्टाचार को द पुलिस पोस्ट ने किया उजागर
जिला प्रभारी मंजू बाघमार ने उचित कार्रवाई को लेकर किया आश्वस्त

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का बडा भ्रष्टाचारी खेल,कौन कौन है सलिप्त...?
खबर का हुआ असर

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एसीबी की टीम आज

स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) में पहुंची। जहां चीफ इंजीनियर के निजी सचिव विमलेश शर्मा के ऑफिस में दस्तावेज खंगाले है। इसके साथ ही विमलेश शर्मा के आवास और अन्य ठिकानों पर भी एसीबी ने छापेमारी की है। इस दौरान आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की जानकारी मिली है। फिलहाल, एसीबी की अलग-अलग टीमें विमलेश शर्मा के कार्यालय, आवास सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। एसीबी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, विमलेश शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर शिकायत मिली थी। एसीबी की इंटेलिजेंस विंग ने इस शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और आज शुक्रवार को विमलेश शर्मा के जयपुर सहित अन्य शहरों में स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई है।

एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित कई जगह रेड मारी है। जयपुर में डीएलबी चीफ इंजीनियर के निजी सचिव, सांचौर नगरपरिषद आयुक्त योगेश आचार्य और दो सहायकों पर एसीबी ने अपना शिकंजा कसा है। टीम ने आज कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस वक्त एसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जयपुर में स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) चीफ इंजीनियर के निजी सचिव के ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल टीमें कार्यालय और आवास सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही इस प्रकरण में एसीबी की ओर से आधिकारिक जानकारी सामने आएगी।

जोधपुर में की थी कार्रवाई

इससे पहले गुरुवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष यूनिट ने जोधपुर में वीआरएस लेने वाली एएनएम की पेंशन बनाने की एवज में 11 हजार रुपए रिश्वत लेने पर ईएसआई अस्पताल के वरिष्ठ सहायक और सीनियर नर्सिंग अफसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वरिष्ठ सहायक ने रिश्वत लेकर सीनियर नर्सिंग अफसर को दी थी। पीड़ित से 35 हजार रुपए पहले ही ले लिए गए थे।

दबिश देकर पकड़ा

ब्यूरो के उप महानिरीक्षक हरेंद्र महावर ने बताया था कि भदवासिया स्कूल के पास विश्वकर्मा नगर निवासी चन्द्रप्रकाश शर्मा से 11 हजार रुपए रिश्वत लेने पर शास्त्री सर्कल के पास मदेरणा कॉलोनी स्थित ईएसआई औषधालय के वरिष्ठ सहायक हरेन्द्रसिंह को रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में उसने बोरानाडा में ईएसआई औषधालय के सीनियर नर्सिंग अफसर जयप्रकाश राजपुरोहित के लिए रिश्वत लेना स्वीकार किया। ब्यूरो ने दोनों की मोबाइल पर बात कराई। हरेन्द्रसिंह ने कहा,ह्यपइसा आयगा। एएनएम वाला आयगा।ह्न तब जयप्रकाश ने उससे कहा, ह्यघरे आ जा।ह्न ब्यूरो की टीम हरेन्द्रसिंह को लेकर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड ले गई और हरेन्द्र से कॉल करवाकर घर की बजाय नजदीकी चौराहे पर बुलाया। तब जयप्रकाश चौहाबो में बजरी चौराहा पहुंचा, जहां हरेन्द्र ने उसे 11 ग्यारह हजार रुपए रिश्वत दी। तभी ब्यूरो के उपाधीक्षक गोरधन चौधरी के नेतृत्व में टीम ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया।

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का बडा भ्रष्टाचारी खेल,कौन कौन है सलिप्त...?
द पुलिस पोस्ट
यूआईटी भीलवाड़ा में पड़ा अजमेर एसीबी का छापा
खबर का हुआ असर

यूआईटी भीलवाड़ा के भ्रष्टाचारी कब जाएंगे पकड़े

इस समाचार पत्र ने अपने संस्करण में ठीक इसी प्रकार के खुलासे करते हुए करीब दो दर्जन समाचार प्रकाशित करके नगर विकास न्यास भीलवाड़ा और नगर परिषद भीलवाड़ा के कई अधिकारी कर्मचारियों के काले कारनामे उजागर किए। यह भी बताया कि किस प्रकार यहां के अधिकारी कर्मचारियों ने वर्षों से यहां एक ही सीट पर जमे रहकर करोड़ अरबो रुपए की दौलत अर्जित कर ली। इस समाचार पत्र के पास ऐसे कई अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं । कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम ने नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के रिकॉर्ड को भी कब्जे में लिया था। आने वाले समय में यहां भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी काली संपत्ति के मालिकों की गर्दन दबोच सकते हैं लेकिन फिलहाल राजस्थान सरकार की जीरो टॉलरेंस पर चलने की बात करने वाली सरकार नगर विकास न्यास भीलवाड़ा और नगर परिषद भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि की तरफ आंख उठाकर नहीं देख रही है जबकि समाचार पत्र लगातार सबूत के साथ खबर प्रकाशित कर रहा है। इससे पहले भी समाचार पत्र में छापी गई हर खबर सच साबित हुई है।

यूआईटी भीलवाड़ा का नया कारनामा आया सामने,
अब तिलक नगर योजना के मुआवजे में आया घोटाला और भ्रष्टाचार का प्रकरण
खबर का हुआ असर

यूआईटी भीलवाड़ा : यहां भ्रष्टाचार पर होता है फुल टॉलरेंस, नियमों से नहीं होते काम, नियम विरुद्ध रुकते नहीं
संविदा कर्मी ऑपरेटर्स पर मेहरबान यूआईटी, पहले हटाया फिर लगाया, इनके पास है करोड़ों की संपत्ति
मुआवजे के नाम पर करोड़ों का खेल , यूआईटी भीलवाड़ा को हुआ है अरबों रुपए का नुकसान
खबर का हुआ असर

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक संपादक उपेन्द्रसिंह राठौड़, अम्बर ऑफसेट प्रा।लि।डीएल टॉवर, 3ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र जेएलएन मार्ग जयपुर से मुद्रित एवं भू-तल ऑरबिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित, 99280-96524, पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार, अनिल मलिक (सहसंपादक) 8696750000, पंकज गर्ग (प्रबंध संपादक) 01482-455184, 9214417111